



2024

कक्षा : 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12

पुरानी (Old) + नई (New)

NCERT BOOKS

का चैप्टरवाइज सुव्यवस्थित संकलन

NCERT सार

(समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी NCERT - मूलांश)

NCERT सार
की समस्त 12 पुस्तकों के
निःशुल्क PDF हेतु
देखें कवर पृष्ठ-2

अर्थशास्त्र

NCERT सार के अन्य उपलब्ध विषय

प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास कला एवं संस्कृति पर्यावरण भूगोल (भौतिक एवं विषय)
भूगोल (भारत) जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान भौतिकी एवं रसायन विज्ञान भारतीय राजव्यवस्था

Scan, JOIN & FOLLOW
घटना चक्र CHANNEL

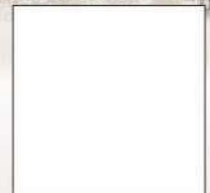
Get News Update, Free PDF, Free Coupon Code and Much more...



ई-बुक पढ़ें
अपडेटेड रहें

ssgcp.com
t.me/ssgcp
ssgc.gs.qa
ssghatnachakra
SamsamayikGhatna

CASH BACK ₹50



See Cover Page - 2

Validity upto April, 2025

© प्रकाशकाधीन :

संस्करण - प्रथम

संस्करण वर्ष - 2024

ले.- SSGC

मूल्य : 350/-

मुद्रक - कोर पब्लिशिंग सोल्यूशन

मुद्रण क्रम - प्रथम

संपर्क-

सम-सामयिक घटना चक्र

188A/128 एलनगंज, चर्चलेन

प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211002

Ph.: 0532-2465524, 2465525

Mob.: 9335140296

e-mail : ssgcald@yahoo.co.in

Website : ssgcp.com

e-shop Website :

shop.ssgcp.com

■ इस प्रकाशन के किसी भी अंश का पुनः प्रस्तुतीकरण या किसी भी रूप में प्रतिलिपिकरण (फोटोप्रति या किसी भी माध्यम में ग्राफिक्स के रूप में संग्रहण, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकीकरण द्वारा जहां कहीं या अस्थायी रूप से या किसी अन्य प्रकार के प्रसंगवश इस प्रकाशन का उपयोग भी) कॉपीराइट के स्वामित्व धारक के लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार से इसके भंग होने या अनुमति न लेने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*इस प्रकाशन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज (इलाहाबाद) के न्यायालय न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

संकलन सहयोग-

■ राजेश शुक्ला

■ अंकित सिंह

■ शशिधर दुबे

■ कैजुल इस्लाम अंसारी

■ आनन्द कुमार प्रजापति

समारम्भ

प्रतियोगिता के रण क्षेत्र में जाने की तैयारी से पहले प्रत्येक प्रतियोगी सैनिक को यह सलाह अवश्य ही दी जाती है कि वह कक्षा 6 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों को आत्मसात कर ले। लेकिन क्या इस सलाह पर अमल करना इतना आसान है? कठिनता ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है कि 7 वर्षों की पाठ्य सामग्री कुछ माह में ही पढ़ लेनी होती है। न केवल पढ़ लेनी है बल्कि विषयों के प्रति समझ भी विकसित कर लेनी है। प्रत्येक प्रतियोगी इस कार्य को प्रारंभ अवश्य करता है परन्तु टास्क की व्यापकता को देखते हुए जल्द ही उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। प्रतियोगी छात्रों की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में थोड़ी सहजता और सरलता उपलब्ध कराने का प्रयास सम सामयिक घटना चक्र ने भी किया है। इस दिशा में कार्य करते हुए हमारे विषय विशेषज्ञों ने एन.सी.ई.आर.टी. कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों के सार-तथ्यों का संकलन पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों में विभाजित करके प्रस्तुत किया है। किसी एक चैप्टर पर यदि एक से अधिक कक्षाओं में सामग्री है तो सभी कक्षाओं की पाठ्य सामग्री को एक स्थान पर प्रस्तुत किया गया है तथा दोहराव को हटा दिया गया है। इस प्रस्तुतीकरण में यह ध्यान रखा गया है कि यदि एन.सी.ई.आर.टी. की विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों में परस्पर कोई भिन्नता हो तो इसका उल्लेख किया जाए। इसी प्रकार अगर किसी तथ्य के संदर्भ में कोई अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो गई हो तो उसका भी उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। कोशिश यह भी की गई है कि परीक्षोपयोगी तथ्यों को ही समाहित किया जाए जिससे परीक्षार्थियों का अधिक समय जाया न हो। यदि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक और किसी अन्य प्रतिष्ठित लेखक की पुस्तक में किसी तथ्य को लेकर भिन्नता हमारे संज्ञान में आयी है तो उसका भी उल्लेख हमने यथा स्थान पर कर दिया है। कुछ चुनिंदा बिंदु पूरे अध्याय को याद रख पाने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसे बिंदुओं को हमने अध्याय की पाठ्य सामग्री के अंत में अध्याय-स्मरणिका शीर्षक के अंतर्गत संजो कर प्रस्तुत किया है।

पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में एक वस्तुनिष्ठ खण्ड है। इस खण्ड में प्रत्येक अध्याय की पाठ्य सामग्री से निर्मित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं उनके व्याख्यात्मक उत्तरों को संकलित किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि पुस्तक में सुधार से संबंधित सुझावों से हमें अवगत कराएं।

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. पारिभाषिक शब्दावली	3-16
2. अर्थशास्त्र : एक परिचय	17-28
3. विकास की समझ	29-36
4. भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा क्षेत्रक	37-65
5. ग्रामीण क्षेत्र का विकास व समस्याएँ	66-91
6. भारत में गरीबी	92-118
7. भारत में मानव पूँजी का निर्माण	119-136
8. राष्ट्रीय आय की संकल्पना	137-172
9. भारत में लोकवित्त	173-203
10. भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग	204-239
11. भारत का औद्योगिक विकास	240-275
12. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था	276-294
13. भारत का विदेशी व्यापार	295-320
14. उपभोक्ता व्यवहार तथा लागत का सिद्धांत	321-360
15. बाजार संतुलन	361-399
16. उपभोक्ता अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा	400-424
17. पर्यावरण एवं धारणीय विकास	425-464

पारिभाषिक शब्दावली (Terminology)

‘NCERT अर्थशास्त्र’ की विभिन्न पुस्तकों में प्रयुक्त अनेक महत्वपूर्ण एवं जटिल शब्दावलियाँ जगह-जगह उल्लिखित हैं। ऐसे छात्र जिनका एकेडमिक अध्ययन अर्थशास्त्र विषय से संबद्ध नहीं होता है, उन्हें ये शब्दावलियाँ समझने के क्रम में कठिनाई की अनुभूति होती है इसीलिए पुस्तक के प्रारंभ में ही इनको व्यवस्थित करना छात्रहित में होगा। एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निम्नलिखित पुस्तकों में ये शब्दावलियाँ (पाठ्य-सामग्री सहित) समाहित हैं—

क्र.सं.	कक्षा	नई/पुरानी	पुस्तक का नाम
1	11	नई	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास
2	12	नई	व्यष्टि अर्थशास्त्र : एक परिचय
3	12	नई	समष्टि अर्थशास्त्र : एक परिचय
4	11	नई	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी

अध्याय अनुक्रमणिका

■ पारिभाषिक शब्दावली

➔ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

➔ व्यष्टि अर्थशास्त्र

➔ समष्टि अर्थशास्त्र

➔ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी

पारिभाषिक शब्दावली (Technical Terminology)

■ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (Development of Indian Economy)

Note : ‘भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास’ नामक पुस्तक से संबंधित सभी शब्दावलियाँ हिंदी वर्णमाला के क्रम (जैसे-स्वरादि अ, आ, इ, ई, उ....तथा व्यंजनादि क, ख, ग,) के अनुसार दी गयी हैं।

☞ **अर्थशास्त्र (Economics)** : व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अन्य संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके, **अर्थशास्त्र** इसका अध्ययन है।

☞ **अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के उद्यम (Informal/Unorganised Sector Enterprises)** : निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः दस से अधिक नहीं होती।

☞ **अदृश्य मर्दे (Invisibles)** : भुगतान संतुलन (BOP) के चालू खाते (Current Accounts) की मर्दे, जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएँ नहीं होतीं। अदृश्य मर्दे प्रायः वे सेवाएँ होती हैं, जैसे- पर्यटन, जहाजरानी और वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएँ। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान-प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण (Money Transfer to Personal Account), सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं।

☞ **अनारक्षण (Dereservation)** : किसी व्यक्ति या उद्योग के समूह को उन वस्तुओं का उत्पादन करने की छूट देना, जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है, जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे।

☞ **अवसर लागत (Opportunity Cost)**: यह किसी कार्य या मूल्यांकन के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है।

- ❶ **अवमूल्यन (Devaluation):** विनिमय दर (Exchange Rate) में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है।
 - ❷ **आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर (Casual Wage Labourer):** अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाला व्यक्ति।
 - ❸ **आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण (Integration of Domestic Economy):** सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके।
 - ❹ **आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) :** सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। इस नीति में आयात नियंत्रण, आयात शुल्क (Import duty) तथा अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
 - ❺ **आयात शुल्क (Tariff):** आयात पर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्यानुसार (Value wise) निर्धारित हो।
 - ❻ **आयात शुल्क बाधाएँ (Tariff Barriers):** सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर।
 - ❼ **आयात लाइसेंस (Import Licensing):** किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति।
 - ❽ **आसियान (Association of South East Asian Nations) :** दक्षिण - पूर्व एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन। इसके सदस्य हैं- थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी (ब्रुनेई), कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम।
-
- ❶ आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं-इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एवं फिलीपींस व इन संस्थापक सदस्यों सहित इस संगठन के कुल 10 स्थायी सदस्य हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता (इंडोनेशिया) में है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है।
-
- ❶ **उत्पादकता (Productivity) :** श्रम या पूंजी की दक्षता (efficiency) में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्रायः श्रम के आगत (Labour input) की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
 - ❷ **उपनिवेशवाद (Colonialism):** युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। इस प्रकार, अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया

जाता था। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है।

- ❶ **उपभोग समुच्चय (Consumption Basket):** किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं-सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। वे हैं- (अ) अनाज (ब) दालें और दूध से बनी चीजें (स) खाद्य तेल (द) सब्जियाँ (ध) वस्त्र आदि।
- ❷ **उद्यम (Enterprise):** किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम, जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है।
- ❸ **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency):** यह एक सरकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है, जिनमें स्व-नियमन तथा बाजार-सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है।
- ❹ **एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act):** इस अधिनियम को व्यापारियों की एकाधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया गया था।
- ❺ **औपचारिक / संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान (Formal Organised Sector Establishments) :** सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिनमें दस या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हों।
- ❻ **अंश/हिस्से/इक्विटी (Equities) :** किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश। इनके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है, और ये लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं।
- ❼ **कर प्रति कर (Cascading Effect):** करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है। उदाहरणार्थ : उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़ कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लग जाता है।
- ❽ **कृषि का व्यावसायीकरण (Commercialisation of Agri- culture) :** स्व-उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यावसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको ऊंची कीमतें देनी प्रारंभ कर दी। उन्हें

नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थीं।

- ☞ **गैर-नवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resources):** वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं है। उनका स्टॉक वृहद होता हुआ भी सीमित है। उदाहरण- जीवाश्म ऊर्जा संसाधन (तेल, कोयला) और लोहा, सीसा, एल्युमीनियम, यूरेनियम खनिज आदि।
- ☞ **गैर-शुल्क बाधाएँ (Non-Tariff Barriers):** सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध। इनमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं।
- ☞ **घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing):** सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना।
- ☞ **जनांकिकीय संक्रमण (Demographic Transition):** जनांकिकीविद् (Demographer) फ्रैंक नोटेस्टीन द्वारा वर्ष 1945 में विकसित अवधारणा। यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु दरों में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण की तीन अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था - पूर्व औद्योगिक, विकासशील तथा आधुनिक समाज। बाद में औद्योगीकरण के उपरांत की अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई।
- ☞ **जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth):** जन्म के समय विद्यमान आयु- विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर, उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा (वर्षों में)।
- ☞ **जी- 8 (G-8) :** आठ देशों का गुट : इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ सम्मिलित हैं। यहां राष्ट्रपक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक-राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहां अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि एक वर्ष है, जो बारी-बारी से सदस्यों को प्रदान की जाती है।

☛ रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को **जी -7** कहा जाने लगा।

- ☞ **जी -20 (G -20):** विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें निम्न देश सम्मिलित हैं— अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रूस, साऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ।

☛ 9 सितंबर, 2023 को G-20 के 18 वें शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली) में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता देने के साथ ही G-20 अब G- 21 बन गया है।

- ☞ **नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) :** भारत में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीतियों के नाम।
- ☞ **निर्यात-आयात नीति/ व्यापार नीति (Export-Import Policy / Trade Policy) :** सरकार की वे आर्थिक नीतियाँ, जो आयात और निर्यात व्यापार को प्रभावित करती हैं।
- ☞ **निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान (Private Sector Establishment) :** निजी व्यक्तियों/समूहों के वामित्व और नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान।
- ☞ **नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources) :** वे संसाधन जो विवेकपूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य आदि ऐसे संसाधन हैं कि यदि इनका अत्यधिक विदोहन (exploitation) नहीं हो, तो ये निरंतर बने रह सकते हैं।
- ☞ **निर्यात शुल्क (Export Duties):** किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर।
- ☞ **निर्यात संवर्धन (Export Promotion):** राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियाँ, जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है।
- ☞ **नियोजक / रोजगारदाता (Employers):** वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं।
- ☞ **नियमित वेतन / मजदूरी पाने वाले श्रमिक (Regular Salaried / Wage Employees):** अन्य लोगों के खेतों/ फर्मों में काम करने वाले व श्रमिक कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी (दिहाड़ी या समय-समय पर नवीनीकृत अनुबंधानुसार [as per contract] नियत भुगतान के रूप में) मिलती है। इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।
- ☞ **परिमाणात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions):** आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष (BOP) के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना।
- ☞ **परिवार (Household):** सामान्यतः एकसाथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह। सामान्यतः

का अर्थ है कि इनके मेहमान परिवार का अंग नहीं होंगे। इसी प्रकार इनमें से यदि कोई अस्थाई रूप से बाहर गया हो, तो उसकी परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

- **पारिवारिक श्रम (Family Labour/Worker):** उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति।
- **पेंशन (Pension):** सेवा निवृत्त श्रमिक को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि।
- **प्रतिष्ठान (Establishment):** ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment):** किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों (Foreign Assets) का निवेश। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं की जाती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, जो अल्पकालिक सट्टेबाजी (Short term betting) के लिए आया है, और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश (FDI) चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में देश में काम आता ही रहेगा।
- **प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):** किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय (NI) और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात।
- **प्रवेश अवरोध (Barriers to Entry):** वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना देते हैं। ये अवरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं।
- **प्रसव/मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate):** यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
- **बजट घाटा (Budgetary Deficit):** सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना।
- **बहुपक्षीय व्यापार संधियां (Multilateral Trade Agreements):** किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान संबंधी व्यापार समझौते।
- **बेहतर अनुपालन (Better Compliance):** सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन।

- **ब्रंटलैंड कमीशन (Brundtland Commission):** संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा वर्ष 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 'धारणीय विकास' (Sustainable Development) की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उद्धरण दिए गए।
- **भुगतान संतुलन (Balance of Payment):** किसी देश के वर्षभर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों (Current & Capital accounts) पर हुए समस्त लेन-देन का सांख्यिकीय सार। इस खाते में अवधिभर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों (Liabilities and Assets) का ब्यौरा होता है। इसलिए यह सदैव संतुलन में रहता है।
- **भूमि / राजस्व बंदोबस्त (Land / Revenue settlement):** देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद, प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में वसूले जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। यह भूखंड चाहे किसी भी किसान के अधिकार में या महल अथवा 'राजस्व ग्राम' या फिर किसी भी जमींदार के अधिकार में रहा हो। यह अधिकार चाहे स्वामित्वाधिकार रहा हो या फिर कर्षण (Right to Cultivation) अधिकार ही हो। इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू-राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा गया है। भारत में तीन प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की गई थीं- (क) स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, (ख) किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व निर्धारण रैयतवाड़ी व्यवस्था (ग) पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था (महालवाड़ी व्यवस्था)।
- **भविष्य निधि (Provident Fund):** कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष- इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है।

☛ NCERT के हिन्दी संस्करण में '....सेवानिवृत्ति' शब्द का ही उल्लेख है जबकि इसी पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में '..... resigns or retires' शब्द का उल्लेख है। इन दोनों शब्दों का अर्थ होगा 'त्यागपत्रित अथवा सेवानिवृत्ति'।

- **मृत्यु दर (Mortality Rate):** यह शब्द 'मृत्यु' पर ही आधारित है। इसे वर्षभर में प्रति हजार जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्याओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि के कारण, दोनों ही प्रकारों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रुग्णता दर (Morbidity Rate) से भिन्न है। रुग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है।

- ❶ **मुद्रास्फीति (Inflation):** सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि।
- ❷ **योजना आयोग (Planning Commission):** भारत सरकार द्वारा गठित एक संगठन। यह देश के सभी संसाधनों के अधिकतम संतुलित और युक्तियुक्त प्रयोग की योजनाएँ बनाने का कार्य करता है। इसे देश के विकास पथ की वरीयताएँ भी निर्धारित करनी होती हैं।

❸ ध्यातव्य है कि, 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग को समाप्त घोषित कर दिया गया।

- ❹ **यूरोपीय संघ (European Union):** यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने के ध्येय से वहाँ के 27 स्वतंत्र देशों द्वारा गठित 'महासंघ'। इसके सदस्य देश हैं- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चैक-गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया बुल्गारिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, रोमानिया।

❺ 31 जनवरी, 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया 'ब्रेक्जिट (Brexit)' के नाम से जानी गई।

- ❻ **राष्ट्रीय उत्पाद/आय (National Product / Income):** किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल।
- ❼ **राज्य विद्युत बोर्ड (State Electricity Boards) :** ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग हैं जो विद्युत उत्पादन, संवहन और वितरण के कार्य करते हैं।
- ❽ **रुग्णता (Morbidity):** बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। यह अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करती है। निरंतर रुग्णता अंततः मृत्यु का रूप भी धारण कर सकती है। हमारे देश में रुग्णता के दो प्रमुख कारण हैं, भीषण श्वास संक्रमण और डायरिया।
- ❾ **वहन क्षमता / धारण क्षमता (Carrying Capacity):** एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता। इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है- घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार, जहाँ पहुँचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है। अतः इस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के कारण निर्वाह से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया (Reproductive Process) बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेशानुसार भिन्न हो

सकती हैं। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण हैं- खाद्य सुलभता, पर्यावरण स्थान आदि।

- ❶ **वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax):** यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर है। यह जुलाई, 2017 को भारत में कई प्रकार के करों जैसे बिक्री कर तथा सकल को समाप्त कर के लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। कर के कई दर हैं जैसे 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत, जो लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। पूरे देश में दर समान रहती है।
- ❷ **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product):** एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य। जी.डी.पी. एक देश की आर्थिक शक्ति का माप है, जबकि जी.डी.पी प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन-स्तर का सूचक माना जाता है।
- ❸ **सकल वर्धित मूल्य (Gross Values Added):** सकल वर्धित मूल्य की गणना सकल घरेलू उत्पाद और सहायिकी में से अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाकर की जाती है।

$$\text{सकल वर्धित मूल्य (GVA)} = \text{सकल घरेलू उत्पाद (GDP)} + \text{सहायिकी (Subsidies)} - \text{अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)}$$
- ❹ **व्यापारी बैंक (Merchant Bankers):** कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश (Share) और ऋण निर्गमन का प्रबंध करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक।
- ❺ **व्यतिक्रम/ चूक (Default):** नियत तिथि पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना। ऋण ये किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (Financial Institution) से सरकार द्वारा लिए गए ऋण भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणी की विश्वसनीयता या 'साख' (Credit) पर आंच आती है।
- ❻ **वित्तीय संस्थान (Financial Institution):** बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आबंटन से जुड़े संस्थान। इनमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान (Investment Institute) सम्मिलित हैं।
- ❼ **वित्तीय नीति (Fiscal Policy):** आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए करों तथा सरकारी व्यय का प्रयोग।
- ❽ **विदेशी विनिमय / विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange):** अन्य देशों की मुद्रा या ब्राण्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (Financial Assets) के माध्यम से आया विदेशी निवेश। इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक फर्मों/ व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता।
- ❾ **विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार (Foreign Exchange Market):** ऐसा बाजार जहाँ आज की नियत दरों (Fixed

rates) पर मुद्राओं की खरीद-बिक्री होती है। पर उस खरीदी-बेची गई मात्रा का वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तिथि को ही किया जाता है।

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones):** ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता। विशेष रूप से बनाये गये आर्थिक क्षेत्र कई देशों में स्थापित हो चुके हैं। ये देश हैं- जनवादी चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि।
- **विनिवेश (Disinvestment):** किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जान-बूझ कर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ-साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी, रचना या प्रबंधन या दोनों, में बदलाव भी किए जा सकते हैं।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio):** रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंकों द्वारा कुल जमाओं और सुरक्षित निधियों (Total Deposits and reserved funds) का तरल रूप (Liquid) में रखा जाने वाला अंश। नकद जमा अनुपात (CRR) के साथ-साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है।
- **सहभागिता (Communes):** जन सहभागिता या चीनी भाषा में **रोन्मिन गोंगशे**। यह चीन में 1958 से 1985 की अवधि में ग्रामीण प्रशासन के तीन स्तरों में से सबसे उच्चतम स्तर था। इस अवधि (1982-85) में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। विशालतम सामुदायिक इकाइयों (कम्यूनों) का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियों तथा उत्पाद दलों (Production Brigades and Production Teams) में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य होते थे।
- **संस्थागत विदेशी निवेशक (Foreign Institutional Investors):** अन्य देशों में आधार (Base) वाले बैंक और गैर-बैंक संस्थान। इनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष (fund) जैसी निवेशक संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं। (स्पष्टतः ये संस्थाएँ देश की अपनी इस प्रकार की संस्थाओं से अलग होती हैं)। शेयर, बॉण्ड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनके निवेश का देश की आर्थिक व्यापारिक परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है।
- **सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation : SAARC):** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इस क्षेत्र के आठ देशों का संघ है। ये देश हैं- भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सार्क दक्षिण एशियाई जनसमुदायों को मैत्री, विश्वास और सूझ-बूझ के आधार

पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक विकास का संवर्धन है।

- **सामाजिक सुरक्षा (Social Security):** वृद्ध, अपंगों, असहायों, विधवाओं और बच्चों के हितार्थ स्थापित / संचालित निजी और सार्वजनिक पेंशन संस्थाएँ। इनमें पेंशन, सेवानुदान, भविष्य निधि (Provident Fund), मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवा आदि सम्मिलित होते हैं।
- **स्वनियोजित (Self-Employed):** अपने खेत/ व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति। इनके कुछ सहायक हो सकते हैं। कब, कहां उत्पादन या विक्रय करें अथवा कैसे कार्य का संपादन करें, इन बातों के विषय में निर्णय की इन्हें स्वतंत्रता रहती है। इनकी आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय या लाभ पर निर्भर रहती है।
- **स्थिरीकरण उपाय (Stabilisation Measures):** भुगतान शेष (BOP) के उतार-चढ़ाव और उच्च स्फीति दर (High Inflation Rate) के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय, राजकोषीय (Fiscal) तथा मौद्रिक नीतिगत (Monetary Policy) उपाय।
- **सेवानुदान (Gratuity):** कर्मचारी के सेवामुक्त होने पर उसे उसकी सेवाओं के लिए नियोक्ता से मिलने वाली एकमुश्त मानार्थ राशि (Lump-sum complimentary amount)।
- **स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange):** ऐसा शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। यहां दलालों (Agents) को कंपनियों के अंशपत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों (Securities) के व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।
- **शहरीकरण (Urbanisation):** किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि। इसके प्रतिनिधि-स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन अवधि वार्षिक, दशकीय या फिर कोई अंतर्वर्ती (Transitional) अवधि हो सकती है।
- **स्टॉक बाजार (Stock Market):** शेयर और स्टॉक के व्यापार के लिए संस्थान।
- **शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate):** एक वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत शिशुओं की संख्या तथा उस वर्ष में जन्में शिशुओं की संख्या का अनुपात गुणा 1000।
- **श्रमिक संघ (Trade Union):** मजदूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मजदूरों द्वारा बनाई गई संस्था।

☞ **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio):** श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या में अनुपात। इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है।

☞ **श्रम कानून (Labour Laws):** सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम।

■ **व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)**

Note : 'व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समस्त शब्दावली अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (जैसे- A, B, C, D X, Y, Z) में दी गई हैं।

☞ **औसत लागत (Average Cost):** निर्गत (Output) की प्रति इकाई की कुल लागत।

☞ **औसत उत्पाद (Average Product):** परिवर्ती आगत (Variable input) का प्रति इकाई निर्गत (Output)।

☞ **औसत संप्राप्ति (Average Revenue):** निर्गत की प्रति इकाई पर कुल संप्राप्ति (Total revenue)।

☞ **लाभ-अलाभ बिंदु (Break-even Point):** पूर्ति वक्र पर वह बिंदु, जिस पर किसी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है।

☞ **बजट रेखा (Budget Line):** इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं, जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है।

☞ **बजट सेट (Budget Set):** बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है, जिन्हें वर्तमान बाजार कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है।

☞ **स्थिर अनुमापी प्रतिफल (Constant Returns to Scale):** उत्पादन फलन (Production Function) का एक गुण, जो उस स्थिति में होता है, जब सभी आगतों (Inputs) में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत (Output) में वृद्धि उसी अनुपात में होती है।

☞ **लागत फलन (Cost Function):** निर्गत के प्रत्येक स्तर पर यह फर्म के लिए न्यूनतम लागत को दर्शाता है।

☞ **हासमान अनुमापी प्रतिफल (Decreasing Returns to Scale):** उत्पादन फलन का एक गुण, जो उस स्थिति में होता है, जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि होने पर अनुपात से कम मात्रा में निर्गत में वृद्धि होती है।

☞ **मांग वक्र (Demand Curve):** मांग वक्र, मांग फलन का ग्राफीय चित्रण (Graphical representation) होता है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की मात्रा को दर्शाता है।

☞ **मांग फलन (Demand Function):** किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता का मांग फलन उस मात्रा को दर्शाता है, जब अन्य वस्तुओं के अपरिवर्तित रहने पर वह उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर चयन करता है।

☞ **संतुलन (Equilibrium):** संतुलन वह स्थिति है, जब बाजार के सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजनाएं एक समान होती हैं।

☞ **अधिमांग (Excess Demand):** यदि किसी कीमत पर बाजार मांग, बाजार पूर्ति से अधिक होती है, तब उस कीमत पर बाजार में अधिमांग की स्थिति मानी जाती है।

☞ **अधिपूर्ति (Excess Supply):** यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति, बाजार मांग से अधिक होती है, तब उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति मानी जाती है।

☞ **फर्म का पूर्ति वक्र (Firm's Supply Curve):** यह निर्गत के उन स्तरों को दर्शाता है, जिनके उत्पादन के लिए चयन लाभ अधिकतम करने वाली कोई फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करेगी।

☞ **स्थिर आगत (Fixed Input):** वह आगत (Input) जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, स्थिर आगत कहलाती है।

☞ **आय प्रभाव (Income Effect):** वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होने पर वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है।

☞ **वर्धमान अनुमापी प्रतिफल (Increasing Returns to Scale):** उत्पादन फलन का एक गुण, जो उस स्थिति में होता है, जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि अनुपात से अधिक होती है।

☞ **अनधिमान वक्र (Indifference Curve):** अनधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का पथ होता है, जिन पर उपभोक्ता उदासीन (Indifferent) रहता है।

☞ **निम्नस्तरीय वस्तुएं (Inferior Goods):** उपभोक्ता की आय के बढ़ जाने पर जिस वस्तु के लिए मांग घट जाती है, उसे निम्नस्तरीय वस्तु कहा जाता है।

☞ **मांग का नियम (Law of Demand):** यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जाती है, जिस दिशा में उसकी आय जाती है, तब उस वस्तु की कीमत के साथ उपभोक्ता की मांग का विपरीत संबंध होता है।

☞ **हासमान सीमांत उत्पाद नियम (Law of Diminishing Marginal Product):** यदि अन्य आगतों के साथ किसी आगत (Input) के उपयोग में वृद्धि करना जारी रखा जाए तो अंततः हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उस आगत के सीमांत उत्पाद में गिरावट आना शुरू हो जाएगा।

☞ **परिवर्ती अनुपात नियम (Law of Variable Proportions):** किसी कारक आगत को जब उत्पादन की प्रक्रिया में कम मात्रा में लगाया जाता है, तब प्रारंभ में उसकी सीमांत उपयोगिता में अधिक वृद्धि होती है; परंतु एक बिंदु पर, पहुंचने के बाद उसका सीमांत उत्पाद कम होने लगता है।

- **दीर्घकाल (Long run):** इसका आशय उस अवधि से है, जिसमें उत्पाद के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- **सीमांत लागत (Marginal Cost):** उत्पादन में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन।
- **सीमांत उत्पाद (Marginal Product):** जब सभी अन्य आगतों को स्थिर रखा जाए, तब आगत में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत (Output) में परिवर्तन।
- **सीमांत संप्राप्ति (Marginal Revenue):** निर्गत के विक्रय (sale of output) में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल संप्राप्ति (Total Revenue) में परिवर्तन।
- **बाजार पूर्ति वक्र (Market Supply Curve):** यह उन निर्गत स्तरों (Output levels) को दर्शाता है, जिसका कुल उत्पादन कोई फर्म बाजार में बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करती है।
- **एकाधिकारी प्रतियोगिता (Monopolistic Competition):** यह वह बाजार संरचना है, जिसमें विक्रेताओं की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन उनके द्वारा बेचा जाने वाला मद्द सजातीय (Homogeneous) नहीं होता।
- **एकाधिकार (Monopoly):** यह वह बाजार संरचना है, जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है तथा बाजार में किसी अन्य विक्रेता के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण होता है।
- **एकदिष्ट अधिमान (Monotonic Preferences):** किसी उपभोक्ता का अधिमान (Preference) केवल उसी स्थिति में एकदिष्ट (Monotonic) होता है, जब किन्हीं दो बंडलों के बीच वह उस बंडल को पसंद करता है, जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम-से-कम किसी एक वस्तु की संख्या अधिक होती है तथा दूसरी वस्तु की संख्या कम नहीं होती।
- **सामान्य वस्तु (Normal Goods):** उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ-साथ जिस वस्तु के लिए मांग भी बढ़ती जाए, उसे सामान्य वस्तु कहा जाता है।
- **सामान्य लाभ (Normal Profits):** लाभ का वह स्तर जिस पर किसी फर्म को केवल उसकी सुनिश्चित लागतें और अवसर लागतें (Opportunity cost) ही प्राप्त हो पाती हैं, उसे सामान्य लाभ कहा जाता है।
- **अवसर लागत (Opportunity Cost):** किसी कार्य की अवसर लागत से अभिप्राय होता है, किसी दूसरे सर्वोत्तम कार्य से मिलने वाले लाभ को छोड़ना।
- **पूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition):** बाजार की वह स्थिति जिसमें (i) सभी फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं तथा (ii) क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं।
- **कीमत की उच्चतम सीमा (Price Ceiling):** किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा को कीमत की उच्चतम सीमा कहा जाता है।
- **मांग की कीमत लोच (Price Elasticity of Demand):** किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच की परिभाषा है, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल।
- **पूर्ति की कीमत लोच (Price Elasticity of Supply):** किसी वस्तु की बाजार कीमत में एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन।
- **कीमत की निम्नतम सीमा (Price Floor):** किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की निम्नतम सीमा।
- **कीमत रेखा (Price Line):** यह समस्तरीय सरल रेखा होती है, जो बाजार कीमत (Market Price) और किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है।
- **उत्पादन फलन (Production Function):** यह उत्पादन की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोजनों (different combinations of the inputs) का प्रयोग करके किया जा सकता है।
- **लाभ (Profit):** यह किसी फर्म की कुल संप्राप्ति (Total revenue) और उसके कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर है।
- **अल्पकाल (Short run):** इससे आशय उस समयावधि से होता है, जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- **उत्पादन बंदी बिंदु (Shut Down Point):** अल्पकाल में यह औसत परिवर्ती लागत वक्र (Average Variable Cost Curve) का न्यूनतम बिंदु होता है तथा दीर्घकाल में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है।
- **प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect):** किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को समायोजित करने पर उस वस्तु की इष्टतम मात्रा (Optional Quantity) में परिवर्तन, जिससे वह उपभोक्ता उसी बंडल को खरीद सके, जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है।
- **अधिसामान्य लाभ (Super-normal Profit):** किसी फर्म के सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ प्राप्त होता है, उसे अधिसामान्य लाभ कहा जाता है।
- **कुल लागत (Total Cost):** कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन लागत का योग।
- **कुल उत्पाद (Total Product):** अन्य सभी आगतों को स्थिर रखकर यदि किसी आगत (Input) में परिवर्तन किया जाता है, तब उस आगत के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग के लिए उत्पादन फलन (Production function) से विभिन्न स्तरों के उत्पादन प्राप्त होते हैं, परिवर्ती आगत और निर्गत (Variable input and output) के बीच के इस संबंध को कुल उत्पाद कहा जाता है।

- **कुल संप्राप्ति (Total Revenue):** किसी फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को बाजार कीमत से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को कुल संप्राप्ति कहा जाता है।
- **कुल संप्राप्ति वक्र (Total Revenue Curve):** यह फर्म की कुल संप्राप्ति और फर्म के निर्गत स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है।
- **परिवर्ती आगत (Variable Input):** वह आगत जिसकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।
- **कुल परिवर्ती लागत (Total Variable Cost):** परिवर्ती आगतों को काम में लाने के लिए किसी फर्म को जिस लागत का वहन करना होता है, उसे कुल परिवर्ती लागत कहा जाता है।

■ समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics)

Note : 'समष्टि अर्थशास्त्र' से संबंधित समस्त शब्दावली अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (जैसे- A, B, C, D....X, Y, Z) में दी गई हैं।

- **एडम स्मिथ (1723-1790):** आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। 'वेल्थ आफ नेशन्स' के लेखक हैं।
- **समस्त मुद्रा संसाधन (Aggregate Monetary Resources):** डाकघर बचत संगठन की अवधि जमा रहित (without time deposits) व्यापक मुद्रा (M3)।
- **आत्म्यंतरिक स्थिरक (Automatic Stabilisers):** निश्चित व्यय और कर नियमों के अंतर्गत जब आर्थिक दशाएँ बदतर स्थिति को प्राप्त होती हैं, तो खर्च में स्वतः बढ़ोत्तरी हो जाती है अथवा करों में स्वतः कमी आ जाती है। अतः अर्थव्यवस्था स्वतः स्थिर दशा को प्राप्त होती है।
- **स्वायत्त परिवर्तन (Autonomous Change):** समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल में परिवर्तनों के मानों में अंतर, जो कि मॉडल के बहिर्जात कारकों के कारण होता है।
- **स्वायत्त व्यय गुणक (Autonomous expenditure Multiplier):** स्वायत्त खर्च में वृद्धि (अथवा कमी) से समस्त निर्गत अथवा आय में वृद्धि (अथवा कमी) का अनुपात।
- **अदायगी संतुलन (Balance of Payments):** किसी भी देश का शेष विश्व के साथ लेने-देने की लेखाओं का संक्षिप्त विवरण।
- **संतुलित बजट (Balanced Budget):** ऐसा बजट जिसमें करों से प्राप्त राजस्व सरकार के व्यय के बराबर है।
- **संतुलित बजट गुणक (Balanced Budget Multiplier):** करों और सरकार के व्यय दोनों में इकाई वृद्धि (Unit increase) या कमी (Decrease) के फलस्वरूप संतुलन निर्गत (Output equilibrium) में परिवर्तन।
- **बैंक दर (Bank Rate):** आरक्षित निधि के अभाव (shortage of reserves) की स्थिति में यदि व्यावसायिक बैंक, रिजर्व बैंक से ऋण लेता है, तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दर।
- **वस्तु विनिमय (Barter Exchange):** मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय।
- **आधार वर्ष (Base Year):** वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) की गणना की जाती है।
- **बंधपत्र (Bonds):** कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरे होने पर भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल (Monetary returns) का वादा लिखित होता है। बंधपत्र (Bonds) फर्म अथवा सरकार के द्वारा लोगों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है।
- **व्यापक मुद्रा (Broad Money):** संकुचित मुद्रा (Narrow Money) + व्यावसायिक बैंकों और डाकघर बचत संगठन द्वारा रखी गई आवधिक जमा (Time deposits)।
- **पूंजी (Capital):** उत्पादन का एक ऐसा कारक, जो स्वयं उत्पादित होता है (Factor of Production which has itself been produced) और आमतौर पर उत्पादन प्रक्रम में इसका पूर्णरूपेण (entirely) उपभोग नहीं होता।
- **पूंजी लाभ/ हानि (Capital gain/ loss):** किसी बंधकपत्रकारी (Bondholder) के धन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी जो कि बाजार में उसके बंधपत्रों की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी के कारण होता है।
- **पूंजीगत वस्तुएं (Capital goods):** ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय उपभोक्ता (Consumer) की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।
- **पूंजीवादी देश अथवा अर्थव्यवस्था (Capitalist Country or Economy):** वह देश जहां अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्मों द्वारा किया जाता है।
- **पूंजीवादी फर्म (Capitalist Firms):** वे फर्म जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं- (a) उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व (b) बाजार के लिए उत्पादन (c) एक दी गई कीमत जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, पर श्रम का क्रय और विक्रय (d) पूंजी का निरंतर संचय (Continuous accumulation of capital)।
- **नकद आरक्षित अनुपात [Cash Reserve Ratio (CRR)]:** व्यावसायिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा राशि का अंश।
- **आय का वर्तुल प्रवाह (Circular Flow of Income):** वह संकल्पना, जिसके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्तुल पथ (Circular way) पर गमन करता है। यह प्रवाह या तो कारक अदायगी (Factor Payments) है या वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय अथवा समस्त उत्पादन के मूल्य के रूप में होता है।
- **टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (Consumer Durables):** ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अतिशीघ्र नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि एक कालावधि (A Period of time) तक टिकती हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं।

- **उपभोक्ता कीमत सूचकांक [Consumer Price Index (CPI)]:** भारित औसत कीमत स्तर में प्रतिशत परिवर्तन (Percentage change in the weighted average price level)। दी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी (given basket of consumption goods) की कीमतों को लेते हैं।
- **उपभोग वस्तुएं (Consumption Goods):** अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है।
- **निगम कर (Corporate Tax):** निगमों के द्वारा अर्जित आय पर लगाए गए कर (या निजी क्षेत्र के फर्म)।
- **करेंसी जमा अनुपात (Currency Deposit Ratio):** लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने पास रखी गई मुद्रा और व्यावसायिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहते हैं।
- **केंद्रीय बैंक से ऋण लेने के माध्यम से घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing through Central Bank Borrowing):** बजटीय घाटे के लिए सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण ग्रहण के माध्यम से वित्त व्यवस्था करती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और फलस्वरूप स्फीति (Inflation) उत्पन्न होती है।
- **मूल्यहास (Depreciation):** मूल्यहास पूंजी स्टॉक में एक कालावधि के अंतर्गत टूट-फूट अथवा अवक्षय (Wear and tear or depletion) है। तिरती विनिमय दरों के अंतर्गत (Under floating exchange rates) विदेशी मुद्रा के रूप में देश की करेंसी की कीमत में कमी। यह विनिमय दरों (Exchange Rate) में वृद्धि के अनुरूप होती है।
- **अवमूल्यन (Devaluation):** आधिकारिक कार्रवाई के माध्यम से अधिकीकृत विनिमय दरों (Pegged exchange rates) के अंतर्गत देशीय करेंसी की कीमत में कमी।
- **आवश्यकताओं का दुहरा संयोग (Double Coincidence of Wants):** ऐसी स्थिति, जहां दो एजेंटों के पास एक-दूसरे के आधिक्य उत्पादन (surplus production) के लिए पूरक मांग हो।
- **आर्थिक एजेंट अथवा इकाइयां (Economic Agents or Units):** आर्थिक एजेंट अथवा आर्थिक इकाइयां ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थाएं होती हैं, जो आर्थिक निर्णय लेती हैं।
- **प्रभावी मांग का सिद्धांत (Effective Demand Principle):** यदि अंतिम वस्तुओं (Final goods) की पूर्ति को अल्पकाल में स्थिर कीमत पर अनंत लोचदार (Infinitely elastic) मान लिया जाए, तो समस्त निर्गत (Aggregate output) का निर्धारण केवल समस्त मांग के मूल्यों द्वारा होता है। इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं।
- **उद्यमवृत्ति (Entrepreneurship):** उत्पादन के दौरान संगठन, समन्वयन और जोखिम वहन (Risk-taking) का कार्य।
- **प्रत्याशित उपभोग (Ex-ante Consumption):** योजनागत उपभोग (Planned Consumption) का मूल्य।
- **प्रत्याशित निवेश (Ex-ante Investment):** योजनागत निवेश का मूल्य।
- **प्रत्याशित (Ex-ante):** किसी परिवर्त (Variable) का उसके वास्तविक मूल्य के विपरीत योजनागत मूल्य।
- **यथार्थ (Ex-post):** किसी परिवर्त का उसके योजनागत मूल्य के विपरीत वास्तविक अथवा उपलब्ध मूल्य।
- **राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि (Expenditure method of calculating national Income):** एक कालावधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतिम व्यय के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि।
- **निर्यात (Exports):** किसी देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री शेष विश्व को करना।
- **बाह्य क्षेत्रक (External sector):** इससे किसी देश और शेष विश्व के बीच आर्थिक लेन-देन सूचित होता है।
- **बाह्य (Externalities):** वैसे लाभ अथवा हानि जो किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या किसी अन्य सत्ता को केवल कुछ व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो रहा है। फर्म अथवा कोई अन्य सत्ता (any other entity) किसी भी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। अगर कोई दूसरे को लाभ अथवा अच्छा बाह्य कारण उपलब्ध करा रहा है, तो प्रथम के द्वारा इसके लिए दूसरे को कोई भुगतान नहीं किया जाता। अगर किसी को दूसरे के द्वारा हानि अथवा खराब बाह्य कारण उपलब्ध कराया जाता है, तो प्रथम को इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती।
- **आदेश मुद्रा (Fiat Money):** वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता (No intrinsic value)।
- **अंतिम वस्तुएं (Final Goods):** वे वस्तुएं जिनमें उत्पादन प्रक्रम में पुनः कोई शिफ्ट (Transformation) नहीं होता।
- **फर्म (Firms):** आर्थिक इकाइयां जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं तथा उत्पादन के कारकों को नियोजित करती हैं।
- **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):** सरकार के खर्च के स्तर तथा अंतरण और कर ढांचे (Tax structure) के स्तर के संबंध में सरकार की नीति।
- **स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate):** दो या दो से अधिक देशों की करेंसियों के बीच की विनिमय दर (Exchnage Rate) जिसका निर्धारण कुछ स्तर पर नियत कर दिया जाता है और जिनके बीच समंजन (Adjustment) कभी-कभी होता है।

- **नम्य/तिरती विनिमय दर (Flexible/ Floating Exchange Rate):** केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना विदेशी बाजार में मांग और पूर्ति (Demand and Supply) की शक्तियों के द्वारा निर्धारित विनिमय दर।
- **प्रवाह (flows):** परिवर्त (Variables) जिसे एक कालावधि में परिभाषित किया जाता है।
- **विदेशी विनिमय (Foreign Exchange):** विदेशी करेंसी परिवर्त दिए हुए देश की देशीय करेंसी को छोड़कर अन्य सारी करेंसियां।
- **विदेशी विनिमय आरक्षित (Foreign Exchange Reserves):** किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित (Hold) विदेशी परिसंपत्तियां (Assets)।
- **उत्पादन के चार कारक (Four Factors of Production):** भूमि, श्रम (Labour), पूंजी (Capital) और उद्यमवृत्ति (Entrepreneurship)। ये सब एकसाथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करते हैं।
- **सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक (GDP Deflator):** नाममात्र (Nominal) सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) से अनुपात।
- **सरकारी खर्च गुणक (Government Expenditure Multiplier):** सरकारी खर्च में प्रत्येक इकाई वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में वृद्धि के आकार को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकीय गुणांक।
- **सरकार (Government):** राज्य, जो देश में कानून व्यवस्था कायम करता है, कर एवं शुल्क लागत है, कानून बनाता है और नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है।
- **महामंदी (Great Depression):** 1930 के दशक की कालावधि में (जो न्यूयॉर्क में वर्ष 1929 में स्टॉक बाजार के तेजी से गिरावट के साथ शुरू हुई) निर्गत (Output) में गिरावट और बेरोजगारी में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई।
- **सकल घरेलू उत्पाद [Gross Domestic Product (GDP)]:** किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समस्त मूल्य। इसमें पूंजी स्टॉक के मूल्यहास के प्रतिस्थापन निवेश (Replacement investment of the depreciation of the capital stock) भी शामिल होते हैं।
- **सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit):** राजस्व प्राप्तियों (Revenue receipts) और पूंजीगत प्राप्तियों (Capital receipts) की अपेक्षा कुल सरकारी व्यय का आधिक्य, जिससे ऋण का सृजन नहीं होता।
- **सकल निवेश (Gross Investment):** पूंजीगत स्टॉक में अभिवृद्धि, जिसमें पूंजी स्टॉक में होने वाले टूट-फूट के लिए प्रतिस्थापन भी शामिल होता है।
- **सकल राष्ट्रीय उत्पाद [Gross National Product (GNP)]:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) + विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय (Net Factor Income)। दूसरे शब्दों में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के सभी नागरिकों की समस्त आय शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में देशीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय शामिल किए जाते हैं और अपने देश के नागरिकों द्वारा विदेशी अर्थव्यवस्था से प्राप्त आय को निकाल दिया जाता है।
- **सकल प्राथमिक घाटा (Gross Primary Deficit):** राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) - ब्याज अदायगी
- **उच्च शक्तिशाली मुद्रा (High Powered Money):** देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई मुद्रा। इसमें मुख्यतः करेंसी आती है।
- **परिवार (Households):** परिवार अथवा व्यक्ति, जो फर्मों को उत्पादन के कारकों की आपूर्ति करते हैं और जो फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं।
- **आयात (Imports):** शेष विश्व से किसी देश द्वारा खरीदी गई वस्तुएं और सेवाएं।
- **राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि (Income Method of Calculating National Income):** एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम कारक अदायगी (Aggregate Value of Final Factor) के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि।
- **ब्याज (Interest):** पूंजी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान।
- **श्रम (Labour):** उत्पादन में प्रयुक्त मानवीय शारीरिक श्रम।
- **भूमि (Land):** उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन नियत अथवा प्रयुक्त (either fixed or consumed)।
- **मध्यवर्ती वस्तुएं (Intermediate Goods):** ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पादन प्रक्रम में होता है।
- **माल सूची (Inventories):** अविक्रीत वस्तुएं (unsold goods), अप्रयुक्त कच्चे माल अथवा अर्ध-निर्मित वस्तुएं जिन्हें कि कोई फर्म एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रखती है।
- **वैध मुद्रा (Legal Tender):** मौद्रिक प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा, जिसे लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता।
- **अंतिम ऋणदाता (Lender of last resort):** किसी देश में मौद्रिक प्राधिकरण का कार्य, जिसमें वह तरलता संकट और बैंक रन की स्थिति में व्यावसायिक बैंकों की शोधन-क्षमता (Solvency) की गारंटी प्रदान करता है।
- **तरलता फंदा (Liquidity Trap):** अर्थव्यवस्था में ब्याज दर की अतिनिम्न स्थिति, जहां प्रत्येक आर्थिक एजेंट

भविष्य में ब्याज दर की वृद्धि की आशा करता है। परिणाम स्वरूप बंधपत्रों (Bonds) की कीमत गिरने लगती है और पूंजी का नुकसान होता है। हर व्यक्ति अपने धन को मुद्रा के रूप में रखने लगता है और मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग (Speculative Demand for Money) असीमित हो जाती है।

- **प्रबंधित तिरती (Managed Floating):** एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्रीय बैंक बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर के निर्धारण की अनुमति प्रदान करता है, किंतु समय-समय पर दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
- **सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume):** अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात।
- **विनिमय माध्यम (Medium of Exchange):** वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा का प्रधान कार्य।
- **मुद्रा गुणक (Money Multiplier):** किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा (High Powered Money) के स्टॉक का अनुपात।
- **संकुचित मुद्रा (Narrow Money):** करेंसी नोट, सिक्के, मांग जमा (demand deposits), जो जनता के द्वारा व्यावसायिक बैंकों में रखे जाते हैं।
- **राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (National Deposable Income):** बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{mp}) + शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण (Other Current Transfers)।
- **निवल घरेलू उत्पाद [Net Domestic Product (NDP)]:** किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समस्त मूल्य, जिसमें पूंजी स्टॉक के मूल्यहास शामिल नहीं होते हैं।
- **परिवारों द्वारा किए गए निवल ब्याज अदायगी (Net Interest Payments made by Households):** परिवार द्वारा फर्मों को किए गए ब्याज भुगतान - परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज भुगतान।
- **निवल निवेश (Net Investment):** पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि। सकल निवेश (Gross investment) के विपरीत, इसमें पूंजी स्टॉक के अवक्षय (Depletion of Capital Stock) के लिए प्रतिस्थापन शामिल नहीं होता।
- **निवल राष्ट्रीय उत्पाद (बाजार कीमत पर) [Net National Product (NNP) (at Market Price)]:** सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) - मूल्य हास (depreciation)।
- **निवल राष्ट्रीय उत्पाद (कारक लागत पर) अथवा राष्ट्रीय आय [NNP (at factor cost) or National Income (NI)]:** बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद - अप्रत्यक्ष कर - उपदान।
- **नाममात्र विनिमय दर (Nominal Exchange Rate):** देशी मुद्रा की इकाईयों की वह संख्या, जो कोई एक इकाई

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए देता है। यह विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा के रूप में कीमत है।

- **नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP):** सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है।
- **गैर-कर अदायगियां (Non-Tax Payments):** परिवारों के द्वारा फर्मों या सरकार को किए गए गैर-कर भुगतान, जैसे कि अर्थदंड (Fines)।
- **खुली बाजार क्रिया (Open Market Operation):** केंद्रीय बैंक के द्वारा आम जनता से बंधपत्र बाजार (Bond market) में सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की खरीद या बिक्री, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी न हो।
- **मितव्ययिता का विरोधाभास (Paradox of thrift):** जब लोग अत्यधिक मितव्ययी हो जाते हैं, तो वे समस्त रूप में बचत कम करते हैं अथवा पूर्ववत् बचत करते हैं।
- **प्राचल शिफ्ट (Parametric shift):** प्राचल के मूल्य में परिवर्तन के कारण आलेख में शिफ्ट।
- **वैयक्तिक प्रयोज्य आय (Personal Disposable Income):** व्यक्तिगत आय (Personal Income) - व्यक्तिगत कर का भुगतान गैर-कर भुगतान।
- **वैयक्तिक आय (Personal Income):** राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ (Undistributed Profits) - परिवार द्वारा निवल ब्याज भुगतान - निगम कर + सरकार और फर्मों से परिवारों को अंतरण भुगतान (Transfer Payments)।
- **वैयक्तिक कर अदायगी (Personal tax Payments):** व्यक्ति पर लगाए गए कर, जैसे- आयकर।
- **माल-सूची में योजनागत परिवर्तन (Planned Change in inventories):** योजनाबद्ध तरीके से माल-सूची के स्टॉक में किए गए परिवर्तन।
- **वर्तमान मूल्य (बंधपत्र का) (Present Value of a Bond):** मुद्रा की वह मात्रा, जिसे आज ब्याज अर्जन परियोजना (Interest Earning Project) में रखने से उतनी ही आय का सृजन होता है, जितनी की किसी बंधपत्र के द्वारा उसकी कालावधि के उपरांत होता है।
- **निजी आय (Private Income):** निजी क्षेत्र को होने वाले निवल घरेलू उत्पाद (NDP) से प्राप्त कारक आय + राष्ट्रीय ऋण ब्याज + विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय + सरकार से चालू अंतरण + शेष विश्व से प्राप्त अन्य निवल अंतरण।
- **राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि (Product Method of Calculating National Income):** किसी कालावधि में अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि।

- ☛ **लाभ (Profit):** उद्यमवृत्ति से प्राप्त सेवा के लिए भुगतान।
- ☛ **सार्वजनिक वस्तु (Public Goods):** सामूहिक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुएं अथवा सेवाएं। किसी को इससे लाभ उठाने से वंचित करना संभव नहीं है और एक व्यक्ति के उपभोग से अन्य के उपभोग में कमी नहीं होती।
- ☛ **क्रय - शक्ति समता (Purchasing Power Parity):** अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत, जिसके अनुसार एक समान वस्तुओं की कीमत विभिन्न देशों में समान रहती है।
- ☛ **वास्तविक विनिमय दर (Real Exchange Rate):** घरेलू वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत।
- ☛ **वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP):** स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादों का मूल्यांकन।
- ☛ **लगान (Rent):** भूमि (प्राकृतिक संसाधनों) की सेवाओं के लिए भुगतान।
- ☛ **आरक्षित जमा अनुपात (Reserve Deposit Ratio):** व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित कुल जमाओं का अनुपात।
- ☛ **पुनर्मूल्यांकन (Revaluation):** अधिकीकृत विनिमय दर (Pegged Exchange Rate) व्यवस्था में विनिमय दर में कमी, जिससे विदेशी करेंसी देशी करेंसी के रूप में सस्ती हो जाती है।
- ☛ **राजस्व घाटा (Revenue Deficit):** राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य।
- ☛ **रिकार्डो समतुल्यता (Ricardian Equivalence):** वह सिद्धांत जिसमें उपभोक्ता अग्रदर्शी (forward looking) होते हैं और आशा करते हैं कि सरकार आज जो ऋण ग्रहण करती है, भविष्य में उसके पुनर्भुगतान (repay) के लिए करों में वृद्धि होगी और तदनुसार वे उपभोग का समंजन (adjustment) करेंगे, जिससे इसका अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा कि कर में वृद्धि से आज होता।
- ☛ **सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio):** व्यावसायिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट तरलता परिसंपत्तियों (Specified Liquid Assets) में निवेश करने के लिए कुल मांग और आवधिक जमा (Total Demand and Time Deposits) का अंश।
- ☛ **स्थिरीकरण (Sterilization):** किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा मुद्रा बाजार में बहिर्जात (Exogenous) अथवा कभी-कभी बाह्य आघातों; जैसे विदेशी विनिमय अंतःप्रवाह (Foreign Exchange Inflow) में वृद्धि के विरुद्ध मुद्रा की पूर्ति को स्थायी रखने के लिए किया गया हस्तक्षेप।
- ☛ **स्टॉक (Stock):** जिन परिवर्तों (Variables) की परिभाषा निश्चित काल बिंदु पर की जाती है।
- ☛ **मूल्य का संचय (Store of Value):** भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य को मूल्य का संचय कहा जाता है।
- ☛ **सरकार और फर्मों से परिवारों को अंतरण भुगतान (Transfer Payments to Households from the Government and Firms):** अंतरण भुगतान ऐसा

भुगतान है, जो कि उसके बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना ही भुगतान करना पड़ता है। **उदाहरणार्थ-** उपहार, छात्रवृत्ति, पेंशन।

- ☛ **अवितरित लाभ (Undistributed Profits):** निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ, जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता।
- ☛ **बेरोजगारी दर (Unemployment Rate):** रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ लोगों की संख्या (जो कि रोजगार की तलाश में हैं) और रोजगार की तलाश में लोगों की कुल संख्या का अनुपात।
- ☛ **मूल्यवर्धन (Value Added):** उत्पादन की प्रक्रिया में फर्म का निवल योगदान। इसकी परिभाषा इस तरह से की जाती है- उत्पादन का मूल्य- उपयोग में लाई गई मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य।
- ☛ **मजदूरी (Wage):** श्रमिक की सेवा के लिए भुगतान।
- ☛ **थोक कीमत सूचकांक [Wholesale Price Index (WPI)]:** भारित औसत कीमत (Weighted Average Price) स्तर में प्रतिशत परिवर्तन। हम उन वस्तुओं के समूह की कीमतों को लेते हैं, जिनकी खरीद-बिक्री थोक में की जाती है।
- ☛ **जान मेनार्ड कीस 1883-1946 (Jon Maynard Keynes 1883-1946) :** समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको ही जाता है।

■ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी (Statistics in Economics)

Note: 'अर्थशास्त्र में सांख्यिकी' से संबंधित समस्त शब्दावली हिंदी वर्णमाला क्रम (जैसे- स्वरादि अ, आ, इ, ई, उ तथा व्यंजनादि क, ख, ग,) के अनुसार दी गयी हैं।

- ☛ **अपवर्जी विधि (Exclusionary Method):** प्रेक्षणों के वर्गीकरण की ऐसी विधि, जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा (Upper Class limit) के बराबर प्रेक्षण (Observation) को उस वर्ग में न रखकर अगले वर्ग में रखा जाता है।
- ☛ **आंकड़े (Statistics):** किसी विषय पर बेहतर समझ अथवा निर्णय लेने के लिए विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित क्रमबद्ध संख्याओं का समुच्चय (प्रायः बड़ी संख्या में)।
- ☛ **उपभोक्ता (Consumer):** जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए या परिवार की आवश्यकताओं के लिए या किसी को उपहार देने के लिए वस्तुएं खरीदता है।
- ☛ **कल्पित माध्य (Assumed Mean):** परिकलन (Calculation) को सरल बनाने के लिए कोई सन्निकट मान (Approximate Value)

- **गुणात्मक तथ्य (Qualitative Data):** गुणों के संबंध में व्यक्त आर्थिक सूचना अथवा आंकड़ें।
- **गुणात्मक वर्गीकरण (Qualitative Classification):** गुण पर आधारित वर्गीकरण। उदाहरण के लिए लिंग वैवाहिक स्थिति आदि के अनुसार लोगों का वर्गीकरण।
- **चर (Variable):** चर एक ऐसी मात्रा है, जिसका प्रयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों के किसी गुण (जैसे- ऊँचाई, भार, संख्या आदि) को मापने के लिए किया जाता है। जिसका मान भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है।
- **चक्रीयता (Cyclicity):** एक से अधिक वर्ष के समय अंतराल के लिए आकड़ों के विचरण में आवर्तिता (Periodicity in data variation)।
- **दुर्लभता (Scarcity):** इसका अभिप्राय उपलब्धता में कमी से है।
- **दशमक (Decile):** ऐसा विभागीय (A Partition) मान जो आंकड़ों को दस समान भागों में बाँटता है।
- **परास (Range):** किसी चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का अंतर।
- **नीति (Policy):** किसी आर्थिक समस्या को हल करने का उपाय।
- **प्रतिदर्श : सर्वेक्षण विधि (Sample : Survey Method):** ऐसी विधि जिसमें समष्टि (totality) से चुने हुए प्रेक्षणों (Observations) को व्यष्टियों के प्रतिनिधि समुच्चय (Representative set of individuals) (प्रतिदर्श) के आधार पर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- **प्रश्नावली (Questionnaire):** अन्वेषण (Enquiry) के विषय पर अन्वेषक (investigator) द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की सूची। उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती है।
- **बारंबारता (frequency Array):** किसी विविक्त चर (discrete variable) का ऐसा वर्गीकरण, जो उनकी संगत बारंबारताओं सहित चर के विभिन्न मानों को दर्शाता है।
- **बारंबारता वक्र (Frequency Curve):** बारंबारता वितरण का एक ऐसा आरेख (diagram) जिसमें वर्ग के मान X-अक्ष पर तथा वर्ग की बारंबारताओं को Y-अक्ष पर आलेखित (Plotted) किया जाता है।
- **बारंबारता वितरण (Frequency Distribution):** मात्रात्मक चर (Quantitative variable) का ऐसा वर्गीकरण, जो यह दर्शाता है कि चर के विभिन्न मान संगत वर्ग की बारंबारताओं सहित विभिन्न वर्गों में कैसे वितरित किए जाते हैं।
- **भारित औसत (Weighted Average):** यहां आंकड़ों के भिन्न-भिन्न बिंदुओं को भिन्न-भिन्न भार देकर औसत का परिकलन किया जाता है।
- **यादृच्छिक प्रतिचयन (Random Sampling):** यह प्रतिचयन (Sampling) की ऐसी विधि है, जिसमें सूचकों के प्रतिनिधि समुच्चय का चयन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यष्टि (individual) को सूचक के रूप में चुने जाने का समान अवसर दिया जाए।
- **वर्ग बारंबारता (Class Frequency):** किसी वर्ग में प्रेक्षणों (observations) की संख्या।
- **वर्ग अंतराल (Class Interval):** ऊपरी और निम्न वर्ग सीमाओं के बीच का अंतर।
- **वर्ग का मध्य बिंदु (Class Midpoint):** किसी वर्ग का मध्य मान उस वर्ग के विभिन्न प्रेक्षणों का प्रतिनिधि (representative) मान है। यह वर्ग की ऊपरी सीमा + वर्ग की निम्न सीमा / 2 के बराबर होता है।
- **वर्गीकरण (Classification):** समान वस्तुओं को समूहों अथवा वर्गों में व्यवस्थित करना।
- **विविक्त चर (Discrete Variable):** ऐसा मात्रात्मक चर (Quantitative Variable) जिसमें कुछ निश्चित मान होते हैं। परिमित 'उछालों' (Finite Jumps) द्वारा यह एक मान से दूसरे मान में परिवर्तित हो जाता है। चर में दो आसन्न मानों (Adjacent values) के बीच मध्यवर्ती मान सम्मिलित नहीं होते।
- **विश्लेषण (Analysis):** किसी आर्थिक समस्या को समझना एवं विभिन्न कारणों के संदर्भ में उसकी व्याख्या करना।
- **विक्रेता (Seller):** वह जो लाभ के लिए वस्तुओं का विक्रय करता है।
- **स्थिरांक (Constant):** स्थिरांक एक मात्रा है, जिसका उपयोग किसी गुण के वर्णन करने के लिए किया जाता है; परंतु परिकलन (Calculation) के दौरान यह परिवर्तित नहीं होता।
- **समावेशी विधि (Inclusive Method):** प्रेक्षणों के वर्गीकरण की ऐसी विधि जिसमें वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के बराबर प्रेक्षणों (Observation) को उसी वर्ग में रखते हैं।
- **समष्टि (Macro):** समष्टि का अर्थ है, वे सभी व्यष्टि/इकाइयां जिनके बारे में सूचना प्राप्त करनी है।
- **सूचक (Indicator):** व्यष्टि/इकाई जिससे इष्ट सूचना प्राप्त की जाती है।
- **सेवाधारी (Service Holder):** वह जो किसी कार्य के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए भुगतान (Payment) प्राप्त करता है।
- **सेवा प्रदाता (Service Provider):** वह जो भुगतान (Payment) लेकर दूसरों को सेवा प्रदान करता है।
- **सांख्यिकी (Statistics):** अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों के संग्रह, संगठन, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण करने की विधि। इसका अभिप्राय आंकड़ों से भी है।
- **सतत चर (Continuous Variable):** ऐसा मात्रात्मक चर जिसका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है।
- **शतमक (Percentiles):** ऐसा मान जो आंकड़ों को सौ बराबर भागों में बाँट देता है; इसलिए आंकड़ों में 99 शतमक होते हैं।

1

अर्थशास्त्र : एक परिचय (Economics : An Introduction)

‘अर्थशास्त्र : एक परिचय’ भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबद्ध प्रश्न बनते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा-6 से कक्षा-12 तक की निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ्य सामग्री समाहित है—

क्रम सं.	कक्षा	नई/पुरानी	पुस्तक का नाम	अध्याय का नाम
1	12	नई	व्यष्टि अर्थशास्त्र	परिचय
2	12	नई	समष्टि अर्थशास्त्र	परिचय

अध्याय अनुक्रमणिका

- सामान्य अर्थव्यवस्था
- अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ
 - ➔ सीमांत उत्पादन संभावना
- आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन
 - ➔ केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
 - ➔ बाजार अर्थव्यवस्था
- सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र
- अर्थशास्त्र की शाखाएँ
 - ➔ व्यष्टि अर्थशास्त्र
 - ➔ समष्टि अर्थशास्त्र
 - (i) आर्थिक एजेंट
 - (ii) समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव
- अध्याय-स्मरणिका
- वस्तुनिष्ठ खंड

सामान्य अर्थव्यवस्था (General Economy)

किसी भी समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों-अध्यापकों जैसी बहुत-सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन-जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे-तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएँ नहीं होती, जिनकी उसे आवश्यकता होती है।

व्यक्ति विशेष (Individual Person) से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है। यह निर्णय लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति अथवा परिवार, समूह, फर्म अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है।

➔ प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग (Consume) करना चाहता है, उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं।

➔ एक कृषक के पास

भूमि का टुकड़ा → थोड़ा अनाज
कृषि के उपकरण → परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा
एक जोड़ी बैल → हो सकती है

➔ बुनकर के पास

कपास → धागा → कपड़ा
बुनने के काम में आने वाले उपकरण
हो सकते हैं।

➔ स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल (Skill) होता है, हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन (Resource) न हो।

संसाधन (Resources) से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। जैसे—भूमि, श्रम, औजार तथा मशीनें इत्यादि।

- इनमें से हर **निर्णायक इकाई** अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ **वस्तुओं व सेवाओं** का उत्पादन कर सकती है तथा अपने **उत्पाद** के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य **वस्तुओं व सेवाओं** को प्राप्त करने के लिए कर सकती है, जिनकी उसे आवश्यकता है।

वस्तु विशेष से अभिप्राय भौतिक मूर्त वस्तुओं, जिनका उपयोग लोगों की **इच्छाओं तथा आवश्यकताओं** की संतुष्टि के लिए किए जाने से है। 'वस्तु' शब्द और 'सेवाएँ' शब्द के अर्थ-भेद को स्पष्ट जानना चाहिए। सेवाओं द्वारा हमें **इच्छाओं तथा आवश्यकताओं** की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ तथा वस्त्रों की तुलना में हम उन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, जो **चिकित्सक** तथा **अध्यापक** हमारे लिए करते हैं। खाद्य पदार्थ और वस्त्र जो उपर्युक्त सेवाओं की **वस्तुओं** के उदाहरण हैं और चिकित्सकों, अध्यापकों के कार्य **सेवाओं** के उदाहरण हैं।

- उदाहरण के लिए, **कृषक परिवार अनाज के उत्पादन** के बाद उसके एक अंश का उपयोग, **उपभोग के लिए** कर सकता है तथा बाकी के उत्पाद का **विनिमय (Exchange) के लिए उपयोग कर सकता है।**
- इसी प्रकार, बुनकर सूत-धागे से जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकतानुसार **वस्तुएँ तथा सेवाएँ** प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये कमा सकती है, जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है, जिनकी उसे आवश्यकता है।
- हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अतः सब लोग मानते हैं कि -

व्यक्ति की आवश्यकताएँ जितनी अधिक होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते।

- कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है, उसकी मात्रा उसे प्राप्त **संसाधनों** की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न **वस्तुओं और सेवाओं** की जो मात्रा वह प्राप्त करता है, वह भी **सीमित** होती है।
- इसके परिणामस्वरूप, वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का

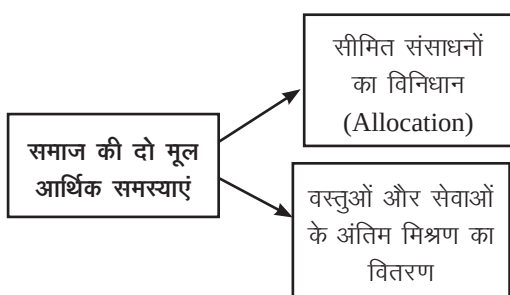
त्याग करके ही **वांछित वस्तुएँ (Desired items)** तथा **सेवाएँ** अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए -

- यदि एक परिवार **बड़ा घर** लेना चाहता है, तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा।
 - यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ **विलासिताओं (luxuries)** को त्यागना पड़ सकता है।
- समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को **संसाधनों की कमी** का सामना करना पड़ता है और इसलिए -

प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट** प्रयोग करना पड़ता है।

- सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी **वस्तु या सेवा** के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं तथा **सेवाओं से संयोजन** की आवश्यकता होती है, जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की **सामूहिक आवश्यकताओं** तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच **सुसंगतता (consistent)** होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए **अनाज की मात्रा** इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के **सामूहिक उपभोग** के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो।
- यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है, जितना **कृषक इकाइयाँ** सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के पास **उपलब्ध संसाधनों** का उन **वस्तुओं तथा सेवाओं** के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिनकी **मांग** बहुत अधिक हो।
- इसके विपरीत, यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी **वस्तुओं तथा सेवाओं** के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे **संसाधनों का पुनः विनिधान (Allocation)** अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

- यही स्थिति अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास **संसाधनों की कमी** होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की **सामूहिक आवश्यकताओं** की तुलना में भी समाज के पास **उपलब्ध संसाधनों** की कमी होती है।
- समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में **विनिधान** (Allocation) करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के **विशिष्ट संयोजन** का उत्पादन (Production of specific combination) होता है। इस प्रकार उत्पादित **वस्तुओं तथा सेवाओं** को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा।



अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं (Central Problems of an Economy)

वस्तुओं तथा सेवाओं का **उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग** जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक समाज को इन **आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों (basic economic activities)** के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही **चयन की समस्या** को जन्म देती है।

- ➡ दूसरे शब्दों में, प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे? **अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्रायः संक्षेप में इस प्रकार होती हैं—**

अर्थव्यवस्था की समस्याएं (Problems of an Economy)

- (1) **किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में?**
- (2) **इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए?**
- (3) **इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए?**
 - (1) प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से **किन-किन वस्तुओं और सेवाओं** का वह कितना उत्पादन करेगा? अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का **अधिक उत्पादन**

किया जाए? कृषिजनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं का? शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के गठन पर, बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर? उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेशपरक वस्तुएं (मशीन आदि)? जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी।

- (2) प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस-किस वस्तु या सेवा में किस-किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। श्रम का अधिक उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का? प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए?
- (3) अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी? अर्थव्यवस्था के उत्पाद को **व्यक्ति विशेष** के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए? किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम? यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो? क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए?

संसाधनों के विनिधान (Allocation of resources) से हमारा आशय यह है कि किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग मात्र प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए ही किया जाता है।

- ➡ प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान (Allocation) कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच, जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए?

सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी **अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं** हैं।

■ सीमांत उत्पादन संभावना (Marginal Production Possibility)

जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी **अर्थव्यवस्था के संसाधन** भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं।

➔ **दुर्लभ संसाधनों** के वैकल्पिक (Alternative) उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है?

- ☞ दूसरे शब्दों में, प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान (Allocation) किस प्रकार करे?

अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का विशिष्ट संयोग उत्पन्न होता है।

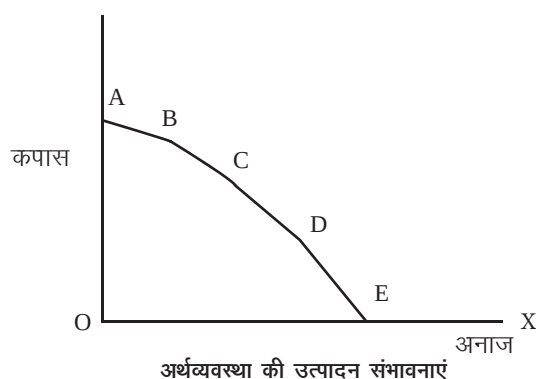
- ☞ उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में **विनिधान (Allocation)** संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के **विभिन्न मिश्रणों** को प्राप्त किया जा सकता है।
- ☞ उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली **सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों** के समूह को **अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट (Production possibility set)** कहते हैं।
- ☞ उदाहरणस्वरूप एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन कर सकती है। निम्न तालिका में अनाज तथा कपास के उन कुछ **संयोगों** को दर्शाया गया है, जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है।

तालिका : उत्पादन संभावनाएं (Production Possibilities)

संभावनाएं	अनाज	कपास
A	0	10
B	1	9
C	2	7
D	3	4
E	4	0

- ☞ सभी **संसाधनों** का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाई है और यदि सभी **संसाधनों** का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए, तो कपास की **अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा** 10 इकाई हो सकती है।
- ☞ अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाई अथवा अनाज की 2 इकाई तथा कपास की 7 इकाई अथवा अनाज की 3 इकाई और कपास की 4 इकाई उत्पादित की जा सकती है। बहुत-सी अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं।

Y



- ☞ उपर्युक्त चित्र में वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु **अनाज तथा कपास** के उस **संयोग** को दर्शाती है, जिसका उत्पादन **अर्थव्यवस्था के संसाधनों** द्वारा संभव है।
- ☞ यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को **सीमांत उत्पादन संभावना (Marginal Production Possibility)** कहते हैं।

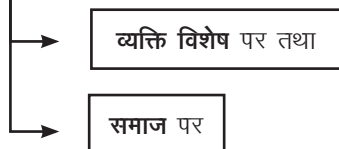
सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास के उन संयोगों को दर्शाती है, जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्णरूप से उपयोग करने पर किया जाता है।

- ☞ सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का वह संयोग दर्शाता है, जो तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह न किया गया हो अथवा उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो।

- ❶ यदि **दुर्लभ संसाधनों** में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी तरह, कपास को अपनाने पर अनाज के लिए कम साधन मिलेंगे। अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, तो **अन्य वस्तुओं की कम मात्रा** प्राप्त की जा सकेगी।
- ❷ इस प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने को **अवसर लागत** कहते हैं।
- ❸ प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में—

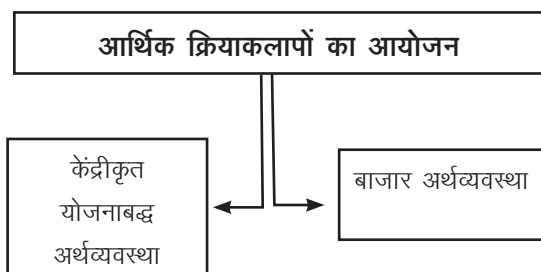
“ बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही **अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या** है। ”

ध्यान दें कि अवसर लागत की संकल्पना लागू होती है—



- ❶ यह संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अर्थशास्त्र में इसके महत्व के कारण **कभी-कभी अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है।**

आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन (Organisation of Economic Activities)



■ केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (The Centrally Planned Economy)

केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तुओं और सेवाओं के **उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग** से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण निर्णय **सरकार द्वारा** किये जाते हैं।

- ➔ केंद्रीय सत्ता, **संसाधनों** का विशेष रूप से **विनिधान (Allocation)** करके **वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम संयोग** प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है; जो पूरे समाज के लिए वांछनीय (Desirable) है।

- ❶ उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख-समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है **जैसे—शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा**, जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है या फिर सरकार स्वयं ऐसी **वस्तुओं तथा सेवाओं** का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है।

■ बाजार अर्थव्यवस्था (The Market Economy)

केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत **बाजार अर्थव्यवस्था** में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण **बाजार की स्थितियों के अनुसार** होता है।

- ➔ अर्थशास्त्र के अनुसार, **बाजार** एक ऐसी **संस्था (Institution)** है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, बाजार **व्यवस्थाओं** का एक ऐसा **समुच्चय** है जहां **आर्थिक अभिकर्ता (Economic Agents)** मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकते हैं।

- ❶ **संस्था को प्रायः** किसी ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका कुछ निश्चित उद्देश्य हो।

- ❶ बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है (जिस पर क्रेता एवं विक्रेता में सहमति होती है)। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय (Exchange) होता है।
- ❶ सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में **मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं** होती हैं; जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। बीसवीं सदी की एक लंबी अवधि तक **केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था** का निकटतम उदाहरण चीन है।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभायी है। तथापि, पिछले दो दशकों में **भारतीय अर्थव्यवस्था** में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गयी है।

सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र (Positive and Normative Economics)

सकारात्मक (Positive) आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक (Normative) आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं? अथवा उसका मूल्यांकन करने का?

- सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि **विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं?** जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि **ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं**
- तथापि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। इनमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता।

अर्थशास्त्र की शाखाएं (Branches of Economics)

परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है : **व्यष्टि अर्थशास्त्र** (Micro Economics) तथा **समष्टि अर्थशास्त्र** (Macro Economics)।

■ व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम **बाजार** में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न **आर्थिक अभिकर्ताओं** के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा **वस्तुओं तथा सेवाओं** की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं?

- इसके विपरीत **समष्टि अर्थशास्त्र** में हम **कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत** स्तर आदि समग्र उपायों

पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं।

- व्यष्टि अर्थशास्त्र** में हमको **‘वैयक्तिक आर्थिक एजेंट’** (Personal Financial Agent) और प्रेरणाओं, जिनसे वे चालित होते हैं, की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। ये ‘व्यष्टि’ (छोटा) एजेंट हैं अर्थात् उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं; उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है।
- दूसरे शब्दों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है जिसमें “आर्थिक भूमिका निभाने वाला” अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होता है (क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी), जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं (उत्पादक या विक्रेता), और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर (उपभोक्ता के रूप में) पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में ‘व्यष्टि’ ही है कि उसे अपने शेयरधारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है जो कि संपूर्ण देश के लिए नहीं होता है।

■ समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics)

समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक **एडम स्मिथ** ने भी यह सलाह दी है कि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु, अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा।

एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक “एन इंक्वायरी इन दू द नेचर एण्ड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस” (1776) विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है।

- समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है; क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है।
- समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं हैं— प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता (‘आर्थिक भूमिका

अदा करने वाले”) कौन होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं करती हैं।

- ☛ विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित किया गया है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा।
- ☛ ये लक्ष्य उन वैयक्तिक, आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं हैं, जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से वैयक्तिक निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं।
- ☛ द्वितीय, समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? स्पष्टतः उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है।
- ☛ इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है। उसका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है।

(i) आर्थिक एजेंट (Economic Agents)

आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है।

- ☛ वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन भी हो सकते हैं, जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है।
- ☛ वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं, जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं; जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज देना है, कितना कर लगाना है।

(ii) समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव (Emergence of Macro Economics)

समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनॉर्ड की प्रसिद्ध पुस्तक “द जनरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी” के वर्ष 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ।

- ☛ कीस से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य (Predominance) था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों

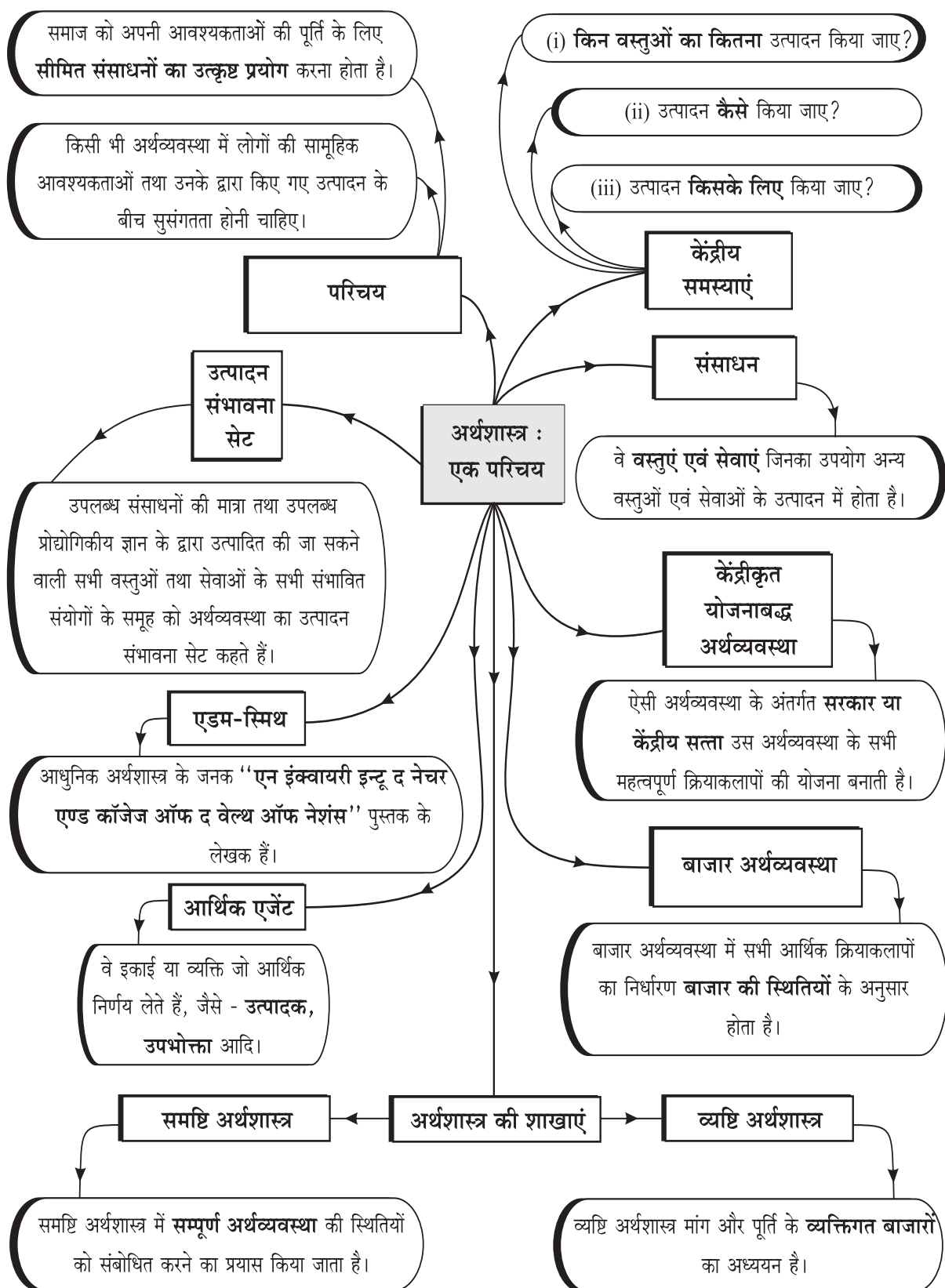
के इस संप्रदाय को **क्लासिकी परंपरा** (Classical Tradition) के रूप में जाना जाता है।

- ☛ ब्रिटिश अर्थशास्त्री **जॉन मेनॉर्ड कीस** का जन्म **1883** ई. में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज, केंब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में वे ‘विशेषज्ञ’ के रूप में नियुक्त हुए।
- ☛ प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े रहे।
- ☛ अपनी पुस्तक ‘**द इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ द पीस**’ (1919) में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी।
- ☛ उनकी पुस्तक ‘**द जनरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी**’ (1936) बीसवीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। कीस **विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज** (Speculator) थे।

➔ **1929 की महामंदी** और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमरीका के देशों में **निर्गत (Output) और रोज़गार** के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा।

- ☛ बाज़ार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था।
- ☛ संयुक्त राज्य अमरीका में **1929** से **1933** तक बेरोज़गारी की दर **3** प्रतिशत से बढ़कर **25** प्रतिशत हो गयी थी (**बेरोज़गारी की दर की परिभाषा** इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं, किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं, से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है, उस रूप में प्राप्त की जाती है)।
- ☛ उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत (Output) में लगभग **33** प्रतिशत की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार्य के संबंध में सोचने को प्रेरित किया।
- ☛ यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी, वहाँ एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। कीस की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर-निर्भरता का परीक्षण करना था।

अध्याय-स्मरणिका (FLASHBACK)



वस्तुनिष्ठ-खंड (Objective Section)

1. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए-

- (1) व्यक्ति अर्थशास्त्र में "वैयक्तिक आर्थिक एजेंट" और प्रेरणाओं, जिनसे वे चालित होते हैं, की प्रकृति का उल्लेख मिलता है।
- (2) व्यक्ति अर्थशास्त्र मांग एवं पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें "आर्थिक भूमिका निभाने वाला" भी व्यक्ति होता है।

कूट :

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

उत्तर—(c)

व्यक्ति अर्थशास्त्र (Micro Economics) "वैयक्तिक आर्थिक एजेंट" और प्रेरणाओं, जिनसे वे चालित होते हैं, की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति अर्थशास्त्र मांग एवं पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें "आर्थिक भूमिका निभाने वाला" अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं। अतः विकल्प (c) सही है।

2. आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) एडम स्मिथ | (b) पॉल सैम्युल्सन |
| (c) जॉन एफ कैनेडी | (d) पॉल क्रुगमैन |

उत्तर—(a)

'एडम स्मिथ' को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे एवं ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।

3. 'एन इन्क्वायरी इन्टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस (An Inquiry into the nature and causes of Wealth of Nations) नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1576 | (b) 1676 |
| (c) 1776 | (d) 1876 |

उत्तर—(c)

एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक "एन इन्क्वायरी इन्टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस" 1776 में प्रकाशित हुई।

4. समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics) का मूल निहित होता है-

- (a) कल्याणकारी अर्थशास्त्र
- (b) अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
- (c) व्यक्ति अर्थशास्त्र
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यक्ति अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों

का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है।

5. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए-

- (1) जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट, इन्टरेस्ट एंड मनी' (The General Theory of Employment, Interest and Money) है।
- (2) इस पुस्तक को 1936 ई. में प्रकाशित किया गया था।

कूट :

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

उत्तर—(c)

जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट, इन्टरेस्ट एंड मनी' है। यह पुस्तक 1936 ई. में प्रकाशित हुई थी। अतः (c) सही विकल्प है।

6. अभिकथन (A) तथा (R) के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए-

अभिकथन (A) : समाष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यक्ति अर्थशास्त्र में निहित होता है।

अभिकथन (R) : इसके अन्तर्गत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है।

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
- (c) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

उत्तर—(a)

समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यक्ति अर्थशास्त्र में निहित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

7. समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के सन्दर्भ में विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए-

- (1) समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय करते हैं।
- (2) समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निर्णयकर्ता द्वारा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है।

- | | |
|------------|------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
|------------|------------|

(c) 1 और 2 दोनों
उत्तर—(c)

(d) न तो 1 और न ही 2

समष्टि अर्थशास्त्र की यह प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत नीतियों का अनुपालन **राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय** करते हैं तथा निर्णयकर्ता द्वारा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है।

8. आर्थिक एजेंट के सन्दर्भ में कौन-सा विकल्प गलत है?

- (a) आर्थिक एजेंट उपभोक्ता हो सकते हैं।
- (b) आर्थिक एजेंट वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं।
- (c) आर्थिक एजेंट सरकार, निगम बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं।
- (d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर—(d)

आर्थिक एजेंट से हमारा आशय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। ये **उपभोक्ता, उत्पादक अथवा सरकार, निगम, बैंक** जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं।

9. क्लासिकीय या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता के अनुसार कौन-सा विकल्प सही है?

- (1) किसी अर्थव्यवस्था में सारे श्रमिक जो कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें कार्य मिलेगा और सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे।
- (2) सरकारी हस्तक्षेप पूर्ण रूप से होता है।
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(a)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में सारे श्रमिक जो कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें कार्य मिलेगा और सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। इसके अन्तर्गत **सरकारी अहस्तक्षेप** की नीति अपनायी जाती है।

10. 'इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ द पीस' (The Economic Consequences of the Peace) पुस्तक के लेखक हैं-

- (a) एस.सी.पीगू
- (b) अल्फ्रेड मार्शल
- (c) जॉन रॉबिन्सन
- (d) जॉन मेनार्ड कीन्स

उत्तर—(d)

'इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ द पीस' पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री 'जॉन मेनार्ड कीन्स' हैं। यह पुस्तक सन् 1919 ई. में प्रकाशित हुई थी।

11. सूची- I एवं सूची-II से सही सुमेलन का चयन कीजिए-

- | सूची-I | सूची- II |
|---|----------|
| A. महामंदी | 1.1776 |
| B. 'इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ दी पीस' | 2.1919 |
| C. 'द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इन्टरेस्ट एंड मनी' | 3.1929 |

D. 'एन इक्वायरी इन्टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस' 4.1936

कूट :

- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (d) | 2 | 3 | 1 | 4 |

उत्तर—(a)

सही सुमेलन-

- A. 'एन इक्वायरी इन्टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस' -- 1776
- B. 'इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ दी पीस' -- 1919
- C. महामंदी -- 1929
- D. 'द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इन्टरेस्ट एंड मनी' -- 1936

12. संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ई. से 1933 ई. तक बेरोजगारी की दर बढ़कर हो गयी थी-

- (a) 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत
- (b) 3 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
- (c) 3 प्रतिशत से 22 प्रतिशत
- (d) 3 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

उत्तर—(d)

1929 ई. से 1933 ई. तक संयुक्त राज्य अमेरिका की बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गयी थी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त निर्गत में लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

13. संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है-

- 1. जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है।
- 2. जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करने में होता है।
- 3. जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात करने में होता है।

उपर्युक्त के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए-

कूट :

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है।

14. वस्तु विशेष से हमारा अभिप्राय है-

- (a) अभौतिक मूर्त वस्तु से
- (b) अभौतिक अमूर्त वस्तु से

- (c) भौतिक मूल वस्तु से
(d) भौतिक अमूल वस्तु से

उत्तर—(c)

वस्तु विशेष से अभिप्राय - भौतिक मूल वस्तुओं से होता है, जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किये जाने से है।

15. व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय है-
1. अपना निर्णय लेने में असक्षम इकाई से है।
2. अपना निर्णय लेने में दूसरे इकाई पर निर्भर इकाई से है।

कूट :

- (a) 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(d)

व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है। सक्षम इकाई के रूप में कोई एक अकेला व्यक्ति अथवा परिवार, समूह, फर्म अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है।

16. समाज के सामने दो मूल आर्थिक समस्याएं हैं-
(a) सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के प्राथमिक मिश्रण का वितरण।
(b) सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण।
(c) सीमित संसाधनों का सीमित प्रयोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण।
(d) असीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण।

उत्तर—(b)

समाज के सामने दो मूल आर्थिक समस्याओं के रूप में- सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण करना है।

17. जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि के अन्तर्गत आता/आते हैं/हैं-
1. वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन।
2. विनिमय।
3. उपभोग।
कूट :
(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक समाज को उन आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।

18. अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के संदर्भ में कौन-सा विकल्प गलत है?
(a) किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में?
(b) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए?

- (c) पड़ोसी देश के साथ संबंध को कैसे सुधारा जाए?
(d) वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए?

उत्तर—(c)

अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्न हैं-

- किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में?
→ इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए?
→ इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए?

19. उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान का उपयोग करके उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संभावित संयोग के समूह को कहते हैं-

- (a) उत्पादन संभावना सेट
(b) उत्पादन प्रतिपूर्ति सेट
(c) उपभोग संभावना सेट
(d) संसाधन संभावना सेट

उत्तर—(a)

उत्पादन संभावना सेट, संसाधनों तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान का प्रयोग करके उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संभावित संयोग को व्यक्त करता है।

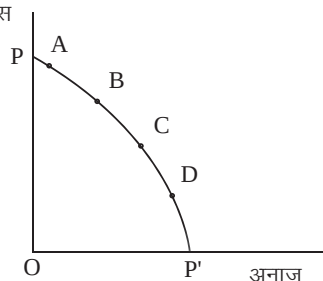
20. अवसर लागत से तात्पर्य है-

- (a) एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग।
(b) एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का संचय।
(c) एक वस्तु की कम मात्रा प्राप्त करने के बदले, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग।
(d) एक वस्तु की कम मात्रा प्राप्त करने के बदले, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का संचय।

उत्तर—(a)

किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गयी मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है।

21. कपास



उपर्युक्त रेखा चित्र में 'PP' वक्र व्यक्त करता है-

- (a) सीमांत प्रतिफल को।
(b) सीमांत उत्पादन संभावना वक्र को।
(c) औसत उत्पादन संभावना वक्र को।
(d) कुल लागत को।

उत्तर—(b)

उपर्युक्त चित्र में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है, जिसे **सीमांत उत्पादन संभावना वक्र** कहते हैं।

22. केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

- सरकार या केंद्रीय सत्ता, उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है।
- किंतु विनिमय तथा उपभोग से संबद्ध निर्णय केंद्रीय सत्ता नहीं

कूट :

- (a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 1
(c) केवल 2 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(b)

केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापों जैसे- वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं।

23. बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है-

- केंद्रीय सत्ता और बाजार की स्थितियों के अनुसार।
- कंपनियों के मालिकों के अनुसार।
- थोक विक्रेताओं के अनुसार।
- बाजार की स्थितियों के अनुसार।

उत्तर—(d)

बाजार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के ठीक विपरीत है।

24. बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है, जिसमें आर्थिक अभिकर्ता-

- मुक्त रूप से धन अथवा उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकता है।
- केवल धन का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकता है।
- केवल वस्तुओं का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकता है।
- केवल सेवाओं का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकता है।

उत्तर—(a)

बाजार व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान-प्रदान कर सकते हैं।

25. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए-

- सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है।

2. इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं

कूट :

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(a)

सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, का अध्ययन किया जाता है।

26. परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु का अध्ययन किन दो शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है?

- व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र।
- समष्टि अर्थशास्त्र और सीमान्त अर्थशास्त्र।
- समष्टि अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र।

उत्तर—(d)

परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषयवस्तु का अध्ययन दो शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।

27. आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए-

- आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम बाजार अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं।
- आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं

कूट :

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(b)

आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह पता लगाते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। बाजार अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है।

28. व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

- अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है?
- बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
- कुल निर्गत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

कूट :

- (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिससे यह विदित होता है कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं।

विकास की समझ

(Understanding The Development)

‘विकास की समझ’ भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबंध प्रश्न बनते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा-6 से कक्षा-12 तक की निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ्य सामग्री समाहित है—

क्रम सं.	कक्षा	नई/पुरानी	पुस्तक का नाम	अध्याय का नाम
1	10	नई	आर्थिक विकास की समझ	विकास
2	11	नई	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	भारत में मानव पूँजी का निर्माण

अध्याय अनुक्रमणिका

■ विकास

➔ आय और अन्य लक्ष्य

■ विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना

➔ आय और अन्य मापदंड के आधार पर

➔ सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर

■ मानव विकास रिपोर्ट

■ विकास की धारणीयता

■ अध्याय-स्मरणिका

■ वस्तुनिष्ठ खंड

विकास (Development)

विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी **आकांक्षाएं और इच्छाएं** हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं? इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए? हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? **विकास** इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है।

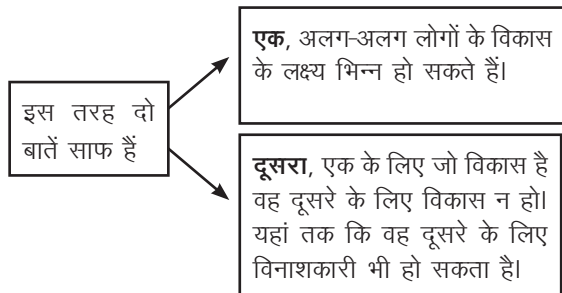
➔ दी गई तालिका के अनुसार कल्पना करने का प्रयास करें कि, लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है तथा उनकी क्या आकांक्षाएं हैं?

तालिका

विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य	
व्यक्ति की श्रेणी	विकास के लक्ष्य/आकांक्षाएं
भूमिहीन ग्रामीण मजदूर	- काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। - स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। - कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं।

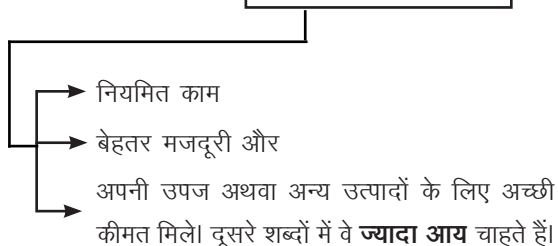
पंजाब के समृद्ध किसान	किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य (Support Price) और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें।
किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं	सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना
भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला	शिक्षा तथा समानता का अवसर उपलब्ध होना
शहरी बेरोजगार युवक	रोजगार का अवसर उपलब्ध हो
शहर के अमीर परिवार का एक लड़का	योग्यता के अनुरूप रोजगार का मिलना
शहर के अमीर परिवार की एक लड़की	- उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। - वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है।
नर्मदा घाटी का एक आदिवासी	जंगल का हरा भरा होना

- इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार **नहीं** इनमें से हर एक अलग-अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं, जो उनके लिए **सर्वाधिक महत्वपूर्ण** हैं, अर्थात् वे चीजें जो उनकी **आकांक्षाओं और इच्छाओं** को पूरा कर सकें। वास्तव में, कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं, जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है।

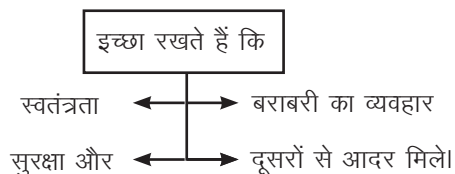


■ आय और अन्य लक्ष्य (Income and Other Goals)

हम अगर एक बार फिर उपर्युक्त तालिका सूची देखें तो एक बात समान पाएंगे : **लोग चाहते हैं कि उन्हें—**



➔ किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, लोग—



- वे **भेदभाव से अप्रसन्न** होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि, कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- उदाहरणस्वरूप अगर आप को कहीं दूर-दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं।

- दूसरी नौकरी में यद्यपि आप को वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित **रोजगार** हो सकता है, जो आपकी **सुरक्षा की भावना** को बढ़ाता है।
- एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी **सुरक्षा और स्वतंत्रता** की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह, विकास के लिए, लोग मिले-जुले लक्ष्यों को देखते हैं।

विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना (Comparision of Different Countries or States)

विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय **सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता** समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से **अधिक विकसित** समझा जाता है।

- यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है **मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना।**
- जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिये, **ज्यादा आय** अपने आप में एक **महत्वपूर्ण लक्ष्य** समझा जाता है।
- एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है।
- लेकिन, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप (Proper measurement) नहीं है। क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है, कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है?
- इसलिए, हम **औसत आय** की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को **प्रतिव्यक्ति आय** भी कहा जाता है।
- विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट** के अनुसार, देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रतिव्यक्ति आय **US \$ 49,300** प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे **समृद्ध अथवा उच्च आय देश** और वे देश जिनकी

प्रतिव्यक्ति आय US \$ 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है; क्योंकि उसकी प्रतिव्यक्ति आय 2019 में केवल US \$ 6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, जिनको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है।

■ आय और अन्य मापदंड के आधार पर (On the Basis of Income and Other Criteria)

व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखने से यह पता चलता है कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं।

- ➡ इन विशेषताओं का निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 2.2 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति-व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में, ये आंकड़े वर्ष 2020-21 की वर्तमान कीमतों पर प्रति-व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (Per Capita Net state Domestic Product) के हैं।

- ➡ इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति-व्यक्ति आय सबसे अधिक -

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23	
तालिका : चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय	
राज्य	प्रतिव्यक्ति आय (रुपयों में) 2020-21
हरियाणा	235707
केरल	205067
बिहार	43605

और बिहार की सबसे कम है। इसका अर्थ है कि औसतन, हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 235707 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 43605 रुपये कमा पाता है।

- ➡ इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति-व्यक्ति आय (Per Capita Income) का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा।
- ➡ अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों को देखते हैं, जो कि तालिका 2.3 में दिये गए हैं।

तालिका : हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े			
राज्य	शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति (2018)	साक्षरता दर % (2017-18)	निवल उपस्थिति अनुपात (प्रति 100 व्यक्ति) उच्चतर आय 14 तथा 15 (वर्ष 2017-18)
हरियाणा	30	80	67
केरल	7	96	77
बिहार	32	71	55

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 P.A. 157 वॉल्यूम 2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (रिपोर्ट संख्या 585)

नोट : मई 2022 की SRS बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार तालिका 2.3 में दिए गये राज्यों में शिशु मृत्युदर क्रमशः निम्न हैं- हरियाणा (28), केरल (6) तथा बिहार (27)।

इस तालिका में प्रयोग किये गए कुछ शब्दों की व्याख्या—

शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) — किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है।

साक्षरता दर — 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात।

निवल उपस्थित अनुपात (Net Present Ratio) — 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु-वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत।

- ➡ इस तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि
 1. केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं।
 2. लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 4 गुना से ज्यादा है।
 3. दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है जैसा तालिका 2.2 में दिखाया गया है।

■ सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर (On the Basis of Public Facilities)

हरियाणा में व्यक्ति की औसत आय केरल के व्यक्ति की औसत आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है।

- ➡ नागरिक, कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है।

➔ उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य (Money) आपके लिए **प्रदूषण मुक्त वातावरण** नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते, जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं।

- ⊖ द्रव्य (Money) आपको **संक्रामक बीमारियों** (Infectious Diseases) से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता।
- ⊖ वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन **वस्तुओं और सेवाओं** को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है।
- ⊖ **केरल में शिशु मृत्यु दर कम है**; क्योंकि यहां **स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं** (Basic facilities) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, कुछ राज्यों में **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (P.D.S.) ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के **स्वास्थ्य और पोषण** स्तर के निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है।
- ⊖ BMI—Body Mass Index एक तरीका है, जिसे वैज्ञानिक, **शरीर द्रव्यमान सूचकांक** (BMI) कहते हैं।

मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)

एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि **आय का स्तर** महत्वपूर्ण है, पर यह **विकास के स्तर** को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे।

➔ ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है।

- ⊖ **स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक**— जैसे हमने **केरल और हरियाणा** की तुलना करने के लिए प्रयोग किये, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में, **स्वास्थ्य और शिक्षा** सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर **विकास के माप** के लिए प्रयोग किया जाने लगा है।
- ⊖ उदाहरण के लिए **यूएनडीपी** द्वारा प्रकाशित **मानव विकास रिपोर्ट** देशों की तुलना लोगों के

- शैक्षिक स्तर
- स्वास्थ्य स्थिति
- और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है।

- ⊖ भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा।

तालिका : वर्ष 2021 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आँकड़े

देश	सकल राष्ट्रीय आय (स. रा.आ.) प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में (2020) क्रय शक्ति क्षमता)	जन्म के समय संभावित आयु	विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक SDG- (4.6)	विश्व में मानव विकास सूचकांक (HDI) का क्रमांक (2021)
श्रीलंका	12,578	76.4	10.8	73
भारत	6,590	67.2	6.7	132
म्यांमार	3,851	65.7	6.4	149
पाकिस्तान	4,624	66.1	4.5	161
नेपाल	3,877	68.4	5.1	143
बांग्लादेश	5,472	72.4	7.4	129

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट, 2021/22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयार्क।

टिप्पणी-

- HDI का अर्थ है **मानव विकास सूचकांक**। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 191 देशों में से है।
- जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, **व्यक्ति की जन्म** के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है।
- प्रतिव्यक्ति आय** की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि **एक डॉलर** किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके।

- ⊖ क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा-सा देश **श्रीलंका** हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है? तालिका 2.4 यह भी दिखाती है कि यद्यपि **नेपाल और बांग्लादेश की प्रतिव्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है**, फिर भी वे **भारत से आयु संभाविता** (Life Expectancy) में पीछे नहीं हैं।

- ❖ **एच.डी.आई.** के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। **मानव विकास रिपोर्ट** में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले, यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है—एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। लोगों का **स्वास्थ्य, उनका कल्याण** सबसे अधिक जरूरी है।

विकास की धारणीयता (Sustainability of Development)

यदि हम मान ले कि एक विदेशी देश काफी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि यहां विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है।

- ➔ लेकिन बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है।

उदाहरण 1- भारत में भूमिगत जल

- ❖ “हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति-उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है।
- ❖ देश का लगभग एक तिहाई भाग, भूमिगत जल भंडारों का अति-उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60 प्रतिशत भाग इस साधन का अति-उपयोग कर रहा होगा।
- ❖ भूमिगत जल का अति-उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है।”

- ❖ भूमिगत जल **नवीकरणीय साधन** (Renewable resources) का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति-उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, **भूमिगत जल** का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति-उपयोग कर रहे होंगे।
- ❖ **गैर-नवीकरणीय साधन** (Non-renewable resources) वे हैं, जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात् समाप्त

हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी।

- ❖ पर्यावरण में गिरावट के परिणाम **राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं** का ख्याल नहीं करते; यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। **विकास की धारणीयता** तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें **वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिल-जुल कर काम कर रहे हैं।**
- ❖ **विकास या प्रगति** का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में, हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं? इसलिए **विकास** पर बहस जारी है।

उदाहरण 2- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए।

तालिका : कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार

क्षेत्र/देश	भंडार (2020) (हजार मिलियन बैरल)	भंडारों के चलने की अवधि (वर्षों में)
मध्य-पूर्व	835.9	82.6
संयुक्त राज्य अमेरिका	68.8	11.4
विश्व	1732.4	53.5

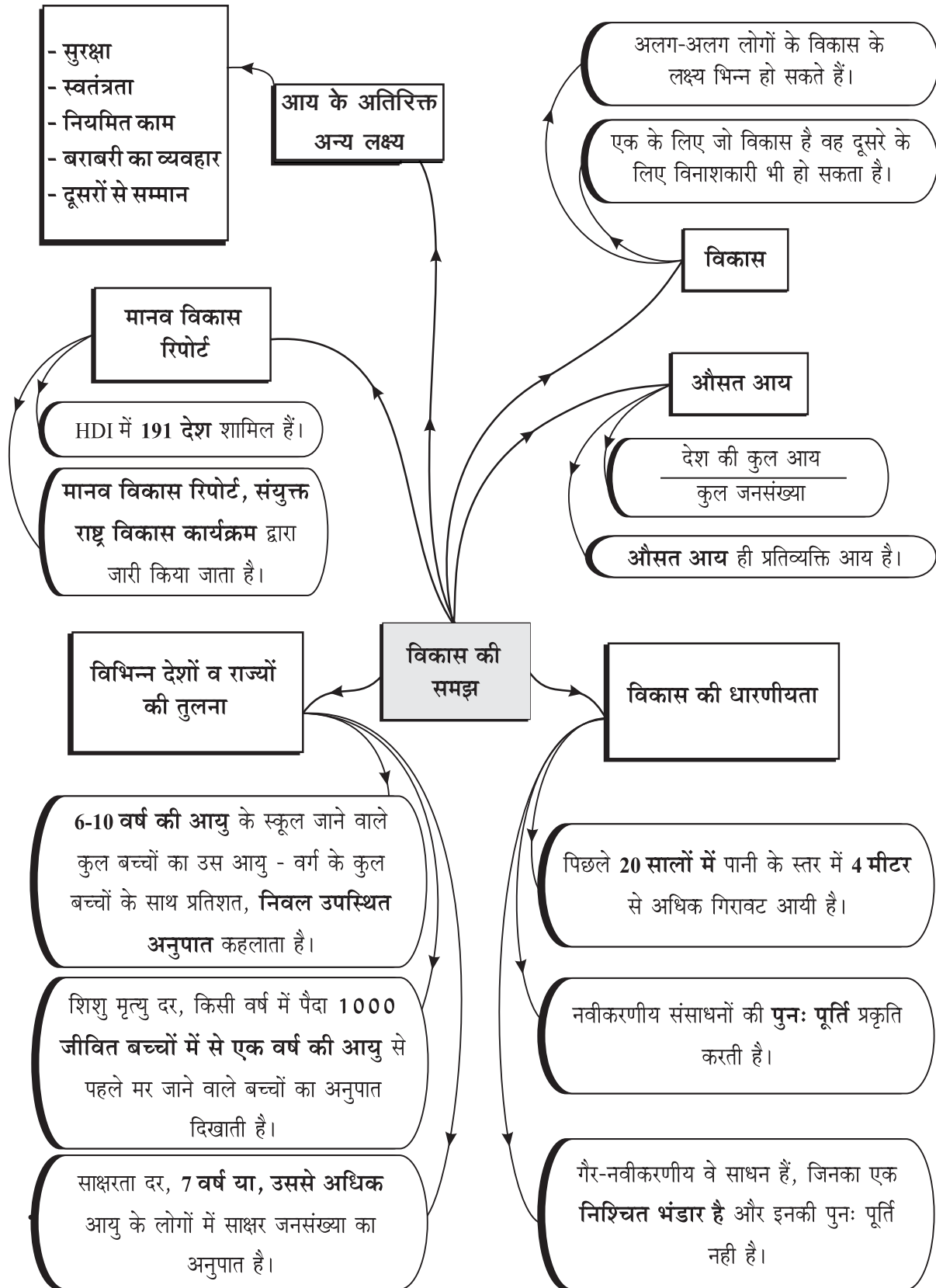
स्रोत : बी.पी. स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, 2021
यह तालिका **कच्चे तेल** के भंडारों के अनुमान (कॉलम 1) को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे? यह संपूर्ण विश्व के लिए है। किंतु अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 53.5 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे।

भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो प्रत्येक पर भार पड़ता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम हैं लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं।

विकास की धारणीयता का प्रश्न, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है।

अध्याय-स्मरणिका (FLASHBACK)



वस्तुनिष्ठ-खण्ड (Objective-Section)

(पूर्णतः NCERT- पाठ्य सामग्री पर आधारित)

1. सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है?

(a) प्रतिव्यक्ति आय (b) औसत साक्षरता
(c) लोगों की स्वास्थ्य स्थिति (d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

किसी देश का विकास, उस देश की प्रतिव्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से निर्धारित किया जा सकता है।

2. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

1. अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं।
2. एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर—(c)

समाज में विकास के मायने अलग-अलग लोगों के लिए भिन्न हो सकते हैं, साथ ही ऐसा कार्य जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है।

3. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाला 'प्रतिव्यक्ति आय' (Per Capita Income), निम्नलिखित में से किससे परिभाषित किया जा सकता है?

(a) किसी व्यक्ति के पास उपस्थित मुद्रा
(b) देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि
(c) देश की कुल जनसंख्या को कुल आय से भाग देने पर प्राप्त राशि
(d) किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

उत्तर—(b)

किसी देश की प्रतिव्यक्ति आय, उस देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जा सकती है।

4. 'विश्व विकास रिपोर्ट' (World Development Report) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?

(a) विश्व बैंक (World Bank)
(b) यू.एन.डी.पी. (United Nations Development Programme)
(c) विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)
(d) नीति आयोग (NITI Aayog)

उत्तर—(a)

विश्व बैंक समूह के द्वारा 'विश्व विकास रिपोर्ट' (World Development Report) जारी की जाती है।

5. प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें—

1. भारत के सभी राज्यों में (प्रति-व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर) प्रतिव्यक्ति आय एक समान है।
2. भारत अपने सभी पड़ोसी देशों में प्रतिव्यक्ति आय के मामले में निचले पायदान पर है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर—(d)

प्रतिव्यक्ति आय की गणना, देश की कुल निवल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। जब यह देश के किसी राज्य के संदर्भ में हो तो उसे राज्य के 'निवल-राज्य घरेलू उत्पाद' को राज्य की जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। अतः सभी राज्यों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति आय होती है। अतः कथन 1 और कथन 2 असत्य हैं।

6. 'मानव विकास रिपोर्ट' (Human Development Report) निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?

(a) विश्व बैंक (World Bank)
(b) यू.एन.डी.पी. (United Nations Development Programme)
(c) विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)
(d) नीति आयोग (NITI Aayog)

उत्तर—(b)

'मानव विकास रिपोर्ट' (Human Development Report) यू.एन.डी.पी. के द्वारा प्रकाशित की जाती है।

7. 'मानव विकास रिपोर्ट' में यूएनडीपी के द्वारा निम्नलिखित में से किस आयाम/किन आयामों को शामिल किया जाता है?

1. शैक्षिक स्तर 2. स्वास्थ्य स्थिति

3. प्रतिव्यक्ति आय

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(d)

यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर की जाती है।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- हाल के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 20 सालों में भूमिगत जल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है।
- देश का लगभग एक तिहाई भाग, भूमिगत जल भण्डारों का अति-उपयोग कर रहा है।
- भूमिगत जल का अति-उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में हो रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(d)

पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग एक तिहाई भाग, भूमिगत जल भण्डारों का अति-उपयोग कर रहा है। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

9. निम्नलिखित में से कौन-सा/से 'गैर-नवीकरणीय साधन' का/के उदाहरण है/हैं?

- भूमिगत जल
- कच्चा तेल (Crude Oil)
- लौह अयस्क
- सूर्य की ऊर्जा
- घरों में उपयोग की गई विद्युत

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर—(b)

जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति या देश अपना विकास करता है उसे उसके विकास के साधन कहते हैं। ये साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला **नवीकरणीय** - ऐसे साधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग कर सकें अर्थात् जो काल एवं स्थान के अनुसार मात्रात्मक रूप में परिवर्तित हों, परंतु उसकी कुल मात्रा एक समान रहे, **नवीकरणीय साधन** कहलाते हैं।

दूसरा **गैर-नवीकरणीय साधन** वो हैं, जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भण्डार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती।

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- नवीकरणीय साधन - इन साधनों का पृथ्वी पर एक निश्चित भण्डार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं सकती।
- गैर-नवीकरणीय - ऐसे साधन जिनकी पुनः पूर्ति केवल प्रकृति करती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर—(d)

नवीकरणीय साधन वे हैं जिनकी पुनः पूर्ति केवल प्रकृति करती है। गैर-नवीकरणीय संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। अतः दोनों असत्य हैं।

11. कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- भारत जैसे देश कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं।
- भारत जैसे देश कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भण्डार तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(b)

भारत के पास पर्याप्त तेल भण्डार नहीं है, यह इसके आयात पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भण्डार तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं।

12. निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है?

- (a) बांग्लादेश (b) श्रीलंका
(c) नेपाल (d) पाकिस्तान

उत्तर—(b)

मानव विकास के दृष्टिकोण से श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। मानव विकास सूचकांक - 2023 में **भारत - 128**, **नेपाल - 138**, **पाकिस्तान - 156** तथा **श्रीलंका - 73**वें स्थान पर हैं।

13. कपास (Cotton) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

- यह एक प्राकृतिक उत्पाद है।
- कपास के पौधों की वृद्धि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है।
- कपास के लिए MSP (Minimum Support Price) की घोषणा कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर—(a)

कपास की खेती एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतया, प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा क्षेत्रक

(The Nature and Sectors of The Indian Economy)

‘भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा क्षेत्रक’ भारतीय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबद्ध प्रश्न बनते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ्य सामग्री समाहित है—

क्रम सं.	कक्षा	नई/पुरानी	पुस्तक का नाम	अध्याय का नाम
1	10	नई	आर्थिक विकास की समझ	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
2	10	पुरानी	हमारी अर्थव्यवस्था : एक परिचय	अर्थव्यवस्था का अध्ययन
3	11	पुरानी	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	रोजगार - संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे तथा आधारिक संरचना

अध्याय अनुक्रमणिका

■ अर्थव्यवस्था के स्वरूप

➔ राज्य की भूमिका के आधार पर

- (i) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
- (ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था
- (iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था

➔ विकास क्रम के आधार पर

- (i) विकसित अर्थव्यवस्था
- (ii) कम विकसित अर्थव्यवस्था
- (iii) विकासशील अर्थव्यवस्था

■ आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक

➔ आर्थिक गतिविधि आधारित क्षेत्रक

- (i) प्राथमिक क्षेत्र (ii) द्वितीयक क्षेत्र
- (iii) तृतीयक क्षेत्र

(a) उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्त्व

(b) अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं?

- (b-i) संगठित क्षेत्रक
- (b-ii) असंगठित क्षेत्रक

➔ स्वामित्व आधारित क्षेत्रक

- (i) सार्वजनिक क्षेत्रक
- (ii) निजी क्षेत्रक

■ आधारिक संरचना

➔ आधारिक संरचना की प्रासंगिकता

➔ आधारिक संरचना की स्थिति

➔ आधारिक संरचना की श्रेणियाँ

(i) ऊर्जा क्षेत्र में आधारिक संरचना की स्थिति

- (a) ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत
- (b) व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति
- (c) ऊर्जा/विद्युत

► विद्युत क्षेत्रक की कुछ चुनौतियाँ

(ii) स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति

- (a) निजी क्षेत्रक में स्वास्थ्य आधारिक संरचना
- (b) भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था
- (c) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारिक संरचना के सूचक : एक मूल्यांकन
- (d) शहरी-ग्रामीण तथा धनी-निधन विभाजन
- (e) महिला स्वास्थ्य

■ व्यावसायिक संरचना

➔ श्रमिक और रोजगार

(i) लोगों की रोजगार में भागीदारी

(ii) स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक

(iii) फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार

➔ संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना

➔ भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण

➔ बेरोजगारी

➔ सरकार और रोजगार सृजन

■ अध्याय-स्मरणिका

■ वस्तुनिष्ठ खंड

अर्थव्यवस्था के स्वरूप (Forms of Economy)

जिस ढाँचे के अंतर्गत एक देश की **समस्त आर्थिक - क्रियाओं** का वर्णन किया जा सकता है उसे ही **अर्थव्यवस्था** कहा जाता है। अतः सरल शब्दों में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत **मूलतः इन आर्थिक क्रियाओं** (Economic activities) की प्रकृति को समझना ही हमारा उद्देश्य है। अर्थव्यवस्थाओं के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं—

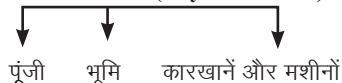
■ राज्य की भूमिका के आधार पर (Based on the role of The State)

(i) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

एक **पूँजीवादी अर्थव्यवस्था** की मुख्य विशेषताएं हैं :

- (अ) उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में **निजी उद्यम** (Private Enterprise) का पाया जाना।
- (ब) **कीमत-यंत्र** का चलना जिसके माध्यम से **क्रेता और विक्रेता** इस बात का निर्धारण करते हैं कि बाजार में किन-किन **वस्तुओं व सेवाओं** को, कितनी-कितनी मात्राओं में और किन-किन कीमतों पर बेचा और खरीदा जाएगा। **'निजी उद्यम'** से तात्पर्य उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली से है, जो **'पूँजी'** (पूँजी उत्पादन के लिए आवश्यक सब प्रकार की सम्पत्तियों के लिए एक सामान्य नाम है) के **निजी स्वामित्व** पर आधारित होती है—

भौतिक परिसम्पत्तियाँ (Physical Assets)



के रूप में हो सकती हैं अथवा यह मुद्रा और उन अन्य **वित्तीय परिसंपत्तियों** (Financial Assets) के रूप में भी हो सकती हैं जो **फर्मों और व्यवसायों** के स्वामित्व एवं संचालन के लिए आवश्यक होती हैं।

- ➔ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर **पूँजी के स्वामियों** का ही नियंत्रण होता है, जो अपने **निजी हित या लाभ** के लिए काम करते हैं।
- ⊕ आजकल लगभग सभी आधुनिक समाज में **उपभोक्ताओं** की रक्षा करने, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित बनाने, तथा **पर्यावरण** को प्रदूषित होने से बचाने जैसे कुछ विशेष सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से राज्य द्वारा निजी लाभ के उद्देश्य को नियंत्रित किया जाता है और उसे एक सीमा के भीतर रखा जाता है।

पूँजीवादी (या विकसित) अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं

- ➔ संयुक्त राज्य अमेरिका और
- ➔ यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड) आदि।

(ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है **सार्वजनिक उद्यम** का पाया जाना अथवा उत्पादक क्रियाओं के **लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूँजी पर राज्य का स्वामित्व**। **बाजार शक्तियों** (Market forces) के स्वतंत्र संचालन के स्थान पर समाजवादी **अर्थव्यवस्थाएं, उत्पादन और वितरण के सरकारी नियोजन पर निर्भर** करती हैं।

- ➔ समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्रेताओं व विक्रेताओं की दृष्टि से लाभदायक माना जाता है। इस आधार पर आर्थिक निर्णय लेने (दूसरे शब्दों में जिसे **मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियाँ** कहा जाता है) के महत्त्व को अधिक तेजी से महसूस किया जा रहा है।

- ⊕ **सोवियत संघ (यूनियन) और चीन** ये दोनों ही **समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं** वाले देश हैं, किंतु जहाँ **सोवियत संघ** एक विकसित अर्थव्यवस्था है वहीं **चीन** विकासशील अर्थव्यवस्था है।

(iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

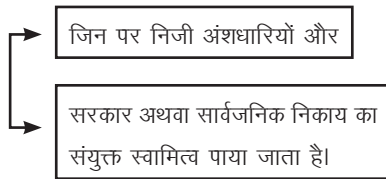
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण **उद्यमों, अर्थात् फर्मों व व्यवसायों पर समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं** की तरह ही राज्य का स्वामित्व होता है, जबकि अन्य उद्यमों पर **पूँजीवादी अर्थव्यवस्था** की तरह **निजी स्वामित्व** ही होता है। इसे हम एक **मिश्रित अर्थव्यवस्था** का उदाहरण कह सकते हैं।

- ➔ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अथवा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को मिलाकर अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र बनता है।
- ⊕ इन उद्यमों को **सार्वजनिक उद्यम** कहा जाता है, क्योंकि इन पर एक प्रकार से सामान्य जनता का ही स्वामित्व होता है।
- ⊕ निजी क्षेत्र निजी हाथों के उन उद्यमों से मिलकर बनता है जिन पर या तो स्वामियों के रूप में अथवा कंपनियों के अंशधारियों (Shareholders) के रूप में व्यक्तियों का स्वामित्व होता है।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का
सर्वप्रमुख उदाहरण है।

- ⊕ भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उद्योग तथा प्रमुख **बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं** शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में **निजी क्षेत्र** भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी कई महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं।
- ⊕ इसके अलावा, भारतीय कृषि लगभग पूरे तौर पर निजी क्षेत्र में ही है और यह काम हमारे किसानों के निजी उद्यम द्वारा ही किया जाता है।

- यद्यपि **भारतीय अर्थव्यवस्था** के कई महत्वपूर्ण उद्योग **निजी क्षेत्र** में हैं और इन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत **स्वामियों अथवा अंशधारियों** के हित में चलाया जाता है, और इन्हें सामाजिक नियंत्रण में रखा जा सकता है।
- भारत में सरकार विभिन्न कानूनी प्रावधानों के माध्यम से **सार्वजनिक हित** में **निजी उद्यमों** की कार्यप्रणाली को **नियंत्रित और निर्देशित** कर सकती है।
- सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व वाली संस्थाओं के अलावा, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी भी फर्म हैं-



- ये फर्म न तो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और न ही निजी क्षेत्र में, अतः इन्हें अर्थव्यवस्था के **'संयुक्त क्षेत्र'** (Joint Venture) में माना जा सकता है।
- भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक मजेदार विशेषता यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ फर्म ठीक वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र की कुछ फर्म भी कर रही होती हैं।
- उदाहरण के लिए, **भारतीय इस्पात उद्योग** में सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों (जैसे **हिंदुस्तान स्टील**) और निजी उद्यम (जैसे **टाटा स्टील**) साथ-साथ पाए जाते हैं। इस प्रकार, कार्य कुशलता की दृष्टि से इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक प्रकार की प्रतियोगिता का अवसर बना रहता है।

■ विकास-क्रम के आधार पर (On the Basis of Sequence of Development)

(i) विकसित अर्थव्यवस्था (Developed Economy)

पश्चिम के वे देश जिनका काफी पहले औद्योगीकरण हो चुका है, तथा जापान, कोरिया और एशिया के अन्य नए औद्योगिक देश **विकसित** अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आते हैं।

- ये तुलनात्मक रूप से संपन्न देश हैं, जिनमें एक आधुनिक औद्योगिक समाज की सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं।

(ii) कम विकसित अर्थव्यवस्था (Least Developed Economy)

गरीब देशों में तुलनात्मक रूप से औद्योगिक क्षेत्र छोटा होता है। इन देशों में चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो अथवा कृषि क्षेत्र,

आधुनिक तकनीक के बारे में भी काफी कम जानकारी पाई जाती है। इन गरीब देशों को सामान्यतया **कम विकसित** देश के नाम से जाना जाता है।

(iii) विकासशील अर्थव्यवस्था (Developing Economy)

इनमें से कुछ को **विकासशील अर्थव्यवस्थाएं** कहा जाना चाहिए, क्योंकि चाहे इनके पास एक छोटा-सा ही आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होता है किंतु फिर भी ये औद्योगिकीकरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया में से गुजर रहे होते हैं।

- एक **विकासशील अर्थव्यवस्था** में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र यद्यपि छोटा होता है, किंतु उसका आकार लगातार विस्तृत होता रहता है और परंपरागत कृषि अथवा **ग्रामीण क्षेत्र** लगातार संकुचित होता जाता है।

आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक (Sectors of Economic Activities)

हम लोगों को विभिन्न **आर्थिक गतिविधियों** में कार्यरत पाते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहां तक कि हमारे बोलने में भी। इन्हें समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण **मानदंडों** के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को **क्षेत्रक** भी कहते हैं। **उद्देश्य** और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है।

■ आर्थिक गतिविधि आधारित क्षेत्रक (Economic Activity Based Sectors)

(ii) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं जैसे-**कपास** की खेती। यह एक **मौसमी फसल** है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम **प्राकृतिक** कारकों जैसे-**वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु** पर निर्भर हैं। अतः **कपास** एक **प्राकृतिक उत्पाद** (Natural Product) है।

- इसी प्रकार, **डेयरी उत्पादन** में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद **दूध** भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार, खनिज और अयस्क भी **प्राकृतिक उत्पाद** हैं।

- जब हम **प्राकृतिक संसाधनों** का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे **प्राथमिक क्षेत्रक** की गतिविधि कहा जाता है। क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है, जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश **प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य**

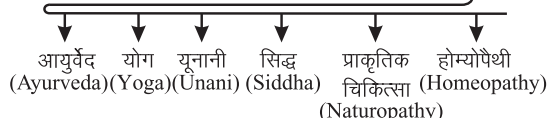
और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को **कृषि एवं सहायक क्षेत्र** भी कहा जाता है।

(ii) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत **प्राकृतिक उत्पादों** के **विनिर्माण** (Manufacturing) प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसीलिए **विनिर्माण** (Manufacturing) की प्रक्रिया अपरिहार्य (Indispensable) है।

➔ यह प्रक्रिया किसी **कारखाने, कार्यशाला या घर** में हो सकती है।

➔ चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं हैं

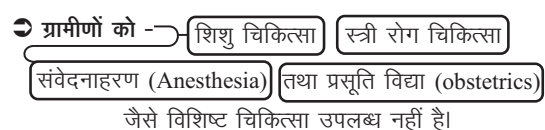


चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे **औद्योगिक क्षेत्र** भी कहा जाता है।

(iii) तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

ये गतिविधियां **प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र** के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः **वस्तुओं** का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि **उत्पादन-प्रक्रिया** में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे—**प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र** द्वारा **उत्पादित वस्तुओं** को थोक एवं **खुदरा** विक्रेताओं को बेचने के लिए **ट्रकों और ट्रेनों** द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है तथा कभी-कभी वस्तुओं को **गोदामों** में भंडारित करने की आवश्यकता होती है।

➔ हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार (**संवाद**) या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है।

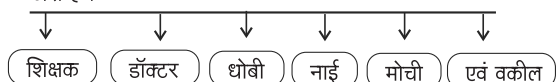


जैसे विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध नहीं है।

चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए **तृतीयक क्षेत्र** को **सेवा क्षेत्र** भी कहा जाता है।

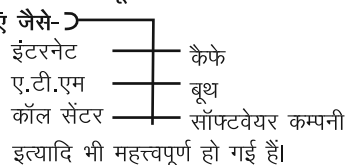
➔ सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं (Essential Services) भी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं।

जैसे हमें—

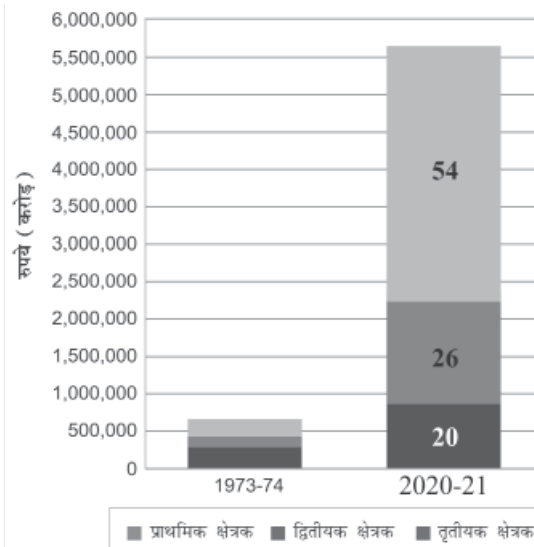


आदि व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखांकन कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है।

➔ वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे—



आलेख : प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा स.घ.उ.



स्रोत - *2020-21 नवीनतम वर्ष है, जिसके लिए तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है।

(a) उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व (Growing Importance of Tertiary Sector)

वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच चालीस वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा।

➔ किसी देश में अनेक सेवाओं जैसे—अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, नगर-निगम, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।

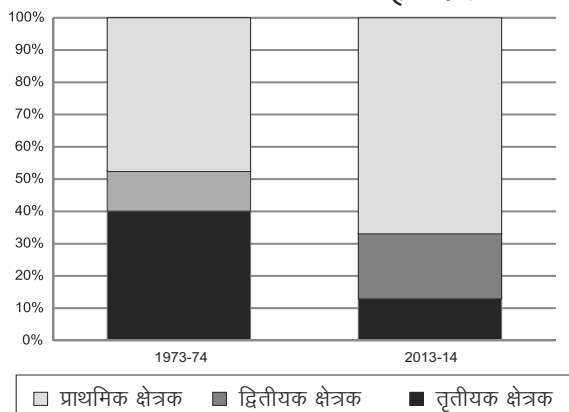
➔ कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी।

➔ जैसे- जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे—रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं।

यह नगरों में विशेषकर बड़े नगरों में द्रुत परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है।

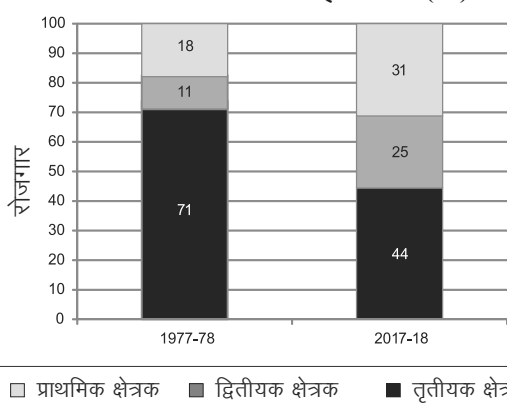
- विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गयी हैं तथा इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है।

स.घ.उ. में क्षेत्रों की हिस्सेदारी



- सेवा क्षेत्रक की सभी सेवाओं में समान रूप से संवृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करती हैं।
- एक ओर सेवाओं की संख्या सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल एवं शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर, बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं।
- वे बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्रक के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है।

रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी (%)



(b) अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? (Where are most of the people employed?)

भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि स.घ.उ. (GDP) में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में

परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

- सकल घरेलू उत्पादक में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई।

- वर्ष 1977-78 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया गया है। जो आज भी प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोजक है।

- देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका स.घ.उ. में योगदान लगभग एक छठां भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का स.घ.उ. में बाकी हिस्सा है।

- कृषि क्षेत्रक के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं।

- इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। (खुली बेरोजगारी)। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised Unemployment) भी कहा जाता है।

- अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, शहरों में सेवा क्षेत्रक में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं।

- इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्रक के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।

(b-i) संगठित क्षेत्र (Organized Sector)

संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य-स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है।

☞ इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों, जैसे-

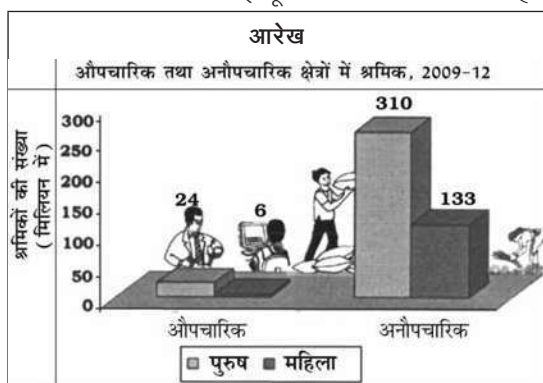
- कारखाना अधिनियम
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
- सेवानुदान अधिनियम
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है।

इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है।

➔ कुछ लोग किसी के द्वारा **नियोजित** नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं। परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और **नियमों एवं विनियमों** का अनुपालन करते हैं।

☞ **संगठित क्षेत्रक** के कर्मचारियों को **रोजगार-सुरक्षा** के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो **नियोक्ता** द्वारा उन्हें अतिरिक्त **वेतन** दिया जाता है।

☞ वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं।



वे **चिकित्सीय** लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक के पेयजल और सुरक्षित कार्य-पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे **सेवानिवृत्त** होते हैं, तो **पेंशन** भी प्राप्त करते हैं।

(b-ii) असंगठित क्षेत्रक (Unorganized Sector)

असंगठित क्षेत्रक छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयों, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होता है। इस क्षेत्रक के **नियम और विनियम** तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले **रोजगार** हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं।

➔ यहां अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। **रोजगार** सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है।

➔ ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदार और

कारीगरों (जैसे-बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार) से रचित होता है। भारत में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं।

☞ शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः

- लघु उद्योगों में श्रमिकों
- निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों
- सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों
- सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों
- वस्त्र निर्माण करने वालों
- कबाड़ उठाने वालों से बना है।

☞ कुछ **मौसमों** में जब काम कम होता है, तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग **नियोक्ता** की पसन्द पर निर्भर होते हैं।

☞ इस **क्षेत्रक** में काफी संख्या में लोग अपने-अपने छोटे कार्यों, जैसे- सड़कों पर विक्रय अथवा **मरम्मत कार्य** में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर **श्रमिकों** को लगाते हैं।

सूची : संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार (दस लाख में)			
रोजगार प्रारूप	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	कुल
औपचारिक	5.09	0.80	5.89
अनौपचारिक	4.46	43.19	47.64
कुल	9.55	43.99	53.53

अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है, प्रतीक्षा कर सकते हैं; लेकिन एक बच्चा नहीं सकता। उसका नाम 'आज' है। ऐसा ही आधारिक संरचना (Infrastructure) के साथ है। (चिली कवि गबरेयल्ला मिस्ट्रल)

■ स्वामित्व आधारित क्षेत्रक (Sectors based on Ownership)

(i) सार्वजनिक क्षेत्रक (Public Sector)

सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

(ii) निजी क्षेत्रक (Private Sector)

निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है।

☞ निजी क्षेत्रक की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए

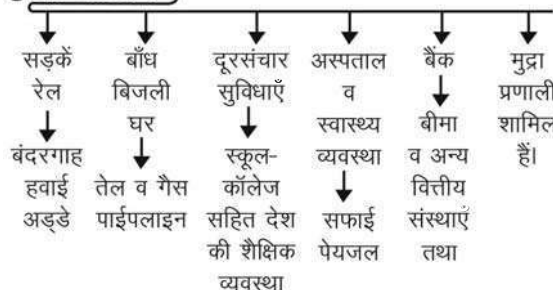
हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है।

- सार्वजनिक क्षेत्रों का अर्थ केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करें या अन्य तरीकों से करती है।
- ऐसी कई चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। उसे सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।
- अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे -
 - सभी के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं
 - गुणात्मक शिक्षा
 - प्राथमिक शिक्षा इत्यादि।
- भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार है। ओडिशा (40) अथवा मध्य प्रदेश (48) का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है।
- सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे- सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन और पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है।

आधारिक संरचना (Infrastructure)

आधारिक संरचना औद्योगिक कृषि उत्पादन, घरेलू एवं विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

➤ इन सेवाओं में-



- इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं।

■ आधारिक संरचना की प्रासंगिकता (Relevance of Infrastructure)

आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है, जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था (Modern Industrial Economy) की कार्यकुशल कार्यप्रणाली निर्भर करती है।

- आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशक दवाइयों और खाद के तीव्र व बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है।
- वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ता है।
- संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती है।
- अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से बुरा असर पड़ सकता है। जलापूर्ति और सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों में कमी आती है और बीमारी के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है।
- जल, सफाई और स्वास्थ्य के बीच इस स्पष्ट संबंध के अलावा परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव भी स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ सकता है।

■ आधारिक संरचना की स्थिति (Status of Infrastructure)

पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना (Infrastructure) को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था। लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है।

- हमारी बहुसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा-खुचा हिस्सा गोबर तथा जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती हैं।
- ईंधन, जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर-दूर तक जाना पड़ता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56 प्रतिशत परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43 प्रतिशत परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है।

- ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत परिवार खाना बनाने में जैव-ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 31 प्रतिशत **ग्रामीण परिवारों** में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 69 प्रतिशत लोग कुआँ, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, पूरे देश में 95.9 प्रतिशत जनसंख्या (98.7% शहरी तथा 94.6% ग्रामीण) बेहतर पेयजल स्रोत वाली घरों में निवासित है, जबकि खाना बनाने हेतु स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले लोग 58.6 प्रतिशत (89.7% शहरी तथा 43.2% ग्रामीण) हैं। यहाँ स्वच्छ जल, ईंधन से तात्पर्य बिजली, एल.पी.जी. प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस से है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत भारतीय घरों में एल.पी.जी. (LPG) की पहुंच है। इसके अलावा प्राथमिक भोजन पकाने के ईंधन के रूप में एल.पी.जी. (LPG) की हिस्सेदारी मार्च, 2020 तक 71 प्रतिशत हो गई है। पक्के घर के साथ स्वच्छ पेय जल अभी भी एक सपना है।

- ग्रामीण इलाकों में केवल 30 प्रतिशत लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थीं।**

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या 70.2 प्रतिशत (81.5% शहरी तथा 64.9% ग्रामीण) है।

- भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई है।
- यह सर्वविदित है कि **आधारिक संरचना (Infrastructure) विकास की नीं** है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है। भारत आधारित संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 5 प्रतिशत निवेश करता है जो कि **चीन और इंडोनेशिया से काफी कम है।**

आर.बी.आई. (RBI) द्वारा अगस्त 2022 में जारी वक्तव्य के अनुसार, आधारिक संरचना में भारत का प्रति व्यक्ति निवेश विश्व में सबसे कम है। (वर्ष 2015 के संदर्भ में 88.6 यू.एस. डॉलर)। भारत वर्तमान में बुनियादी ढांचे पर जी.डी.पी. का मात्र 4.6 प्रतिशत के बराबर निवेश करता है, यदि यह जीडीपी की 6 प्रतिशत के बराबर निवेश करे तो एक अनुमान के मुताबिक भारत वर्ष 2030 तक 7.5 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर की जीडीपी हासिल कर लेगा।

- कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की **तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था** होगी। इसके लिए भारत को **आधारिक संरचना (Infrastructure) सुविधाओं** में निवेश को बढ़ाना होगा।
- किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ-साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। **अल्प आय** वाले देशों के लिये **सिंचाई, परिवहन और बिजली** जैसी **बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं** अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व (**Mature**) होती हैं और उनकी बुनियादी उपयोग के योग्य **मांगों की पूर्ति** होती है, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है और **सेवा** से संबंधित **आधारिक संरचना** की आवश्यकता पड़ती है।
- यही कारण है कि **उच्च आय** वाले देशों में **बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना** का हिस्सा अधिक होता है।
- अतः **आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास** साथ-साथ होते हैं। काफी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है।
- औद्योगिक प्रगति— **बिजली उत्पाद** **परिवहन** और **संचार** के विकास पर निर्भर करती है।
- यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी।

सूची : (विश्व विकास सूचक - 2019)

भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारिक संरचना (Status of Infrastructure in India and other Countries)					
देश	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश	सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाले (%)	सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं का उपयोग करने वाले (%)	मोबाइल प्रयोक्ता/1000 लोग	ऊर्जा की खपत (मिलियन टन के बराबर)
चीन	44	96	72	115	3274
हांग कांग	22	100	91.8	259	31
भारत	30	94	40	87	809
दक्षिण कोरिया	31	98	99.9	130	301
पाकिस्तान	16	35	64	73	85
सिंगापुर	28	100	100	146	88
इंडोनेशिया	34	87	61	120	186

■ आधारिक संरचना की श्रेणियाँ (Categories of Infrastructure)

कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बांटते हैं।

- आर्थिक: ऊर्जा (इसी के अंतर्गत परिवहन व संचार आदि भी आते हैं।)
- सामाजिक: स्वास्थ्य (इसी के अंतर्गत शिक्षा और आवास आदि भी आते हैं।)

(i) ऊर्जा क्षेत्र में आधारिक संरचना की स्थिति (Status of Infrastructure in the Energy Sector)

किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे **खाद, कीटनाशक** और कृषि-उपकरणों के उत्पादन और यातायात (Transportation) में भी **उपयोग** भारी स्तर पर हो रहा है।

➔ घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होती है।

☉ **ऊर्जा के स्रोत**—ऊर्जा के **व्यावसायिक** और **गैर व्यावसायिक** स्रोत होते हैं। **व्यावसायिक स्रोतों** में **ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल और बिजली** आते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है।

☉ ऊर्जा के **गैर-व्यावसायिक स्रोतों** में **जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा-कचरा (Waste) और सूखा गोबर** आते हैं। ये **गैर-व्यावसायिक** हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।

☉ आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत (पनबिजली को छोड़कर) समाप्त हो जाते हैं जबकि गैर-व्यावसायिक या पारंपरिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है।

☉ भारतीय परिवारों में 60 प्रतिशत से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकता के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर हैं।

(a) ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत (Non-Conventional Sources of Energy)

ऊर्जा के **व्यावसायिक** और **गैर-व्यावसायिक** स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं।

☉ ऊर्जा के तीन और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर **गैर-पारंपरिक स्रोत (Non-Conventional sources)** कहते हैं, वे हैं—सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा।

☉ उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा तभी संभव होगा जब कोई सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाये या और भी सस्ती **प्रौद्योगिकी (Technology)** विकसित की जाये।

(b) व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति (Consumption Pattern of Commercial Energy)

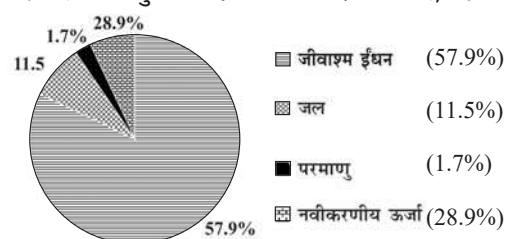
भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का लगभग 74 प्रतिशत व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें सर्वाधिक हिस्सा लिग्नाइट कोयला का है। उसके बाद क्रमशः तेल, प्राकृतिक गैस, जल तथा अन्य और नवीकरणीय ऊर्जा का स्थान है। जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और कृषि का कूड़ा-कचरा आदि गैर-व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का लगभग 26 प्रतिशत से ज्यादा है।

सूची

व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां (% में)				
क्षेत्रक	1953-54	1970-71	1990-91	2020-21
परिवार	10	12	12	26
कृषि	01	03	08	18
उद्योग	40	50	45	41
परिवहन	44	28	22	01
अन्य	5	07	13	14
कुल	100	100	100	100
स्रोत : सी.एस.ओ. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार (2020-21)				

➔ भारत के **ऊर्जा क्षेत्रक** की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थव्यवस्था से भी संबंध है, कि हमें **पेट्रोल और पेट्रोलियम** उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी।

चार्ट : भारत में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत नवंबर, 2022 तक



- उपर्युक्त सूची में **व्यावसायिक ऊर्जा (Commercial Energy)** के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति दी गई है। 1953-54 में परिवहन क्षेत्रक व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लेकिन परिवहन क्षेत्रकों के अंश में निरंतर गिरावट आई है, जबकि घरेलू कृषि तथा अन्य क्षेत्रकों के उपयोग में वृद्धि हो रही है।
- समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में **तेल और गैस** का अंश सबसे अधिक है। आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ-साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है।

(c) ऊर्जा/विद्युत (Energy/Electricity)

ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता की प्रगति का **द्योतक** (indicator of progress) माना जाता है, में बिजली आती है।

- ➔ किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर **सकल घरेलू उत्पाद दर** से ऊंची होती है।

☉ एक अनुमान है कि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि (accretion) का प्रतिवर्ष दर लगभग 12 प्रतिशत होना चाहिए।

► विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियाँ (Some Challenges in Electric Sector)

विभिन्न **पॉवर स्टेशनों** द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोग, उपभोक्ता नहीं करते। उसके एक अंश का उपभोग पॉवर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली के संप्रेषण (Communication) में भी उसका एक हिस्सा खत्म हो जाता है। शेष बिजली हम अपने घरों, ऑफिसों और कारखानों में प्राप्त करते हैं।

- ➔ भारत में **बिजली क्षेत्र** के समक्ष आज कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं।

(क) भारत की वर्तमान **बिजली उत्पादन क्षमता** उच्च आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि (High Economic Potential Growth) के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष मात्र 20 हजार मेगावॉट नई क्षमता जोड़ पाता है। यहां तक कि स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है, क्योंकि बिजलीघर उचित तरीके से नहीं चल रहे।

(ख) राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं, की हानि 20,000 करोड़ से ज्यादा है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है जिससे राज्य विद्युत निगमों को और भी नुकसान होता है।

(ग) बिजली के क्षेत्र में **निजी क्षेत्र** की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेश का भी यही हाल है।

(घ) भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें और लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष है। भारत के थर्मल पॉवर स्टेशन, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं।

☉ इस प्रकार, निरंतर **आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि** से भारत में **ऊर्जा की मांग** में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह **मांग** वर्तमान में उत्पन्न की जा

रही ऊर्जा से बहुत अधिक है। अधिक **सार्वजनिक निवेश**, बेहतर अनुसंधान व **विकास** (Research and Development) के उपाय **तकनीकी खोज और ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत** (Recycled) स्रोतों से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

(ii) स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति (Status of Health Infrastructure)

स्वास्थ्य किसी की सुख-समृद्धि का मापदंड है। **स्वास्थ्य राष्ट्र** की समग्र संवृद्धि और विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। आमतौर पर विद्वान, लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा एवं पोषण स्तर के साथ-साथ संक्रामक (infectious) और असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों द्वारा करते हैं।

- ➔ **स्वास्थ्य आधारित संरचना** के विकास से किसी देश में **वस्तुओं व सेवाओं** के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है।

☉ लोगों को **स्वास्थ्य-सुविधाएं** प्राप्त करने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के **स्वस्थ स्वास्थ्य** जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे।

☉ स्वास्थ्य आधारित संरचना में-

➔ अस्पताल	➔ बेड
➔ डॉक्टर	➔ अस्पतालों में जरूरी उपकरण
➔ नर्स	➔ और एक सुविकसित दवा उद्योग शामिल हैं।
➔ और अन्य अर्द्ध-चिकित्साकर्म	

सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह

स्वास्थ्य	शिक्षा
भोजन में मिलावट	दवाएं तथा जहरीले पदार्थ,
चिकित्सा व्यवसाय	जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़े,
मानसिक अक्षमता	और पागलपन

जैसे स्वास्थ्य संबंधित गंभीर मुद्दों को निर्देशित व विनियमित करे।

- ➔ **केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** परिषद् की सहायता से विस्तृत **नीतियां एवं योजनाएं** विकसित करती हैं। वे सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए **राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों** और अन्य निकायों को **वित्तीय व तकनीकी** सहायता (Financial and Technical Assistance) प्रदान करती है।

☉ पिछले वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य **आधारित संरचना** और **जनशक्ति** को विकसित किया है। **गांव के स्तर** पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की है। भारत में ऐसे

अस्पतालों-तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) की संख्या भी अधिक है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्रक द्वारा चलाये जा रहे हैं।

- ☉ इन अस्पतालों को मेडिकल, दवा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्साकर्म (Paramedic) संचालित करते हैं।
- ☉ स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1951-2018 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों की संख्या 9300 से बढ़कर 53,800 हो गई और अस्पतालों, तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के बेड 1.2 से 7.1 लाख हो गये।
- ☉ 1951-2018 के दौरान नर्सिंगकर्मियों की संख्या 18,000 से 30 लाख हो गई, जबकि एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या 62,000 से 11.5 लाख हो गई। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार से चेचक और स्नायुक रोगों (Neurological Diseases) का उन्मूलन और पोलियो तथा कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन हो गया है।

☛ "नेशनल हेल्थ प्रोफाइल" के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध हैं और इनमें केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है।

सूची

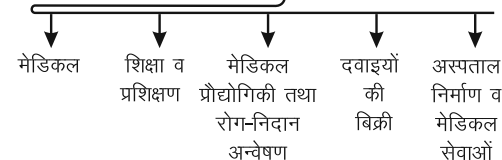
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनात्मक सेवाएं 1951-2018				
मद	1951	1981	2000	2018
सरकारी अस्पताल	2694	6805	15888	25778
सरकारी अस्पताल - दवाखाना में बेड	117000	504538	719861	713986
दवाखाना	6600	16745	23065	27951
सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र	725	9115	22842	25743
उपकेंद्र	-	84736	137311	158417
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-	761	3043	5624
स्रोत : नेशनल कमीशन ऑन मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड हेल्थ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, कई वर्षों के आंकड़े, www.cbhidghs.nic.in				

(a) निजी क्षेत्रक में स्वास्थ्य आधारिक संरचना (Health Infrastructure in Private Sector)

एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है।

उनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का 2/5 वां हिस्सा है। लगभग 60 प्रतिशत दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाये जा रहे हैं। वे 80 प्रतिशत बाह्य रोगियों और 46 प्रतिशत अंतःरोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं।

☉ पिछले वर्षों में निजी क्षेत्रक -



की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

- ➔ 2001-2002 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे; इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे जो समय-समय पर भाड़े के श्रमिकों से काम लेते थे।

(b) भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था (Health System in India)

भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं की तीन स्तरीय व्यवस्था है- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।

☉ प्राथमिक क्षेत्रक सुविधाओं में प्रचलित-

- ➔ स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने की विधि
- ➔ खाद्य पूर्ति तथा उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति तथा मूलभूत स्वच्छता, शिशु एवं मातृत्व देखभाल
- ➔ प्रमुख संक्रामक बीमारियों और चोटों से प्रतिरोध तथा मानसिक स्वास्थ्य का संवर्द्धन और आवश्यक दवाओं का प्रावधान शामिल है।

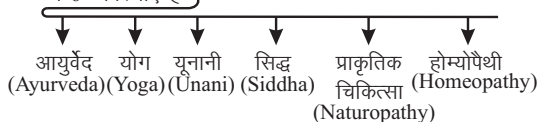
1. ऑक्सीलियरी नर्सिंग मिडवाइफ (ए.एन.एम.) पहला व्यक्ति है, जो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांवों तथा छोटे कस्बों में अस्पताल बनाये गये हैं।
 - ☉ आमतौर पर यहां एक डॉक्टर, एक नर्स और सीमित मात्रा में दवाएं उपलब्ध होती हैं। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और उपकेंद्रों के नाम से जाना जाता है।
2. जिन अस्पतालों में शल्य-चिकित्सा (Surgery), एक्सरे, इ.सी.जी.जैसी बेहतर सुविधाएं होती हैं, उन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं।
3. तृतीयक क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं, जो कि न केवल उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करते और अनुसंधान करते हैं बल्कि वे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ हैं- मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस, बेंगलुरु और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।

सूची

अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचक 2015-17				
सूचक	भारत	चीन	अमेरिका	श्रीलंका
1. शिशु मृत्यु दर/प्रति 1000 जिंदा शिशु पर (2018)	30	7.4	5.6	6.4
2. पांच वर्ष के नीचे मृत्यु दर/प्रति 1000 शिशु पर	36.6	8.6	5	7.4
3. प्रशिक्षित परिचारिका द्वारा जन्म (2016)	81.4	100	99	99
4. प्रतिरक्षित शिशु (डी. पी.टी.) (%) (2018)	89	99	94	99
5. जी.डी.पी. (%) के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी (2016)	3.7	5.7	17.0	3.9
6. जेब से बाहर का व्यय, स्वास्थ्य पर वर्तमान व्यय के प्रतिशत के रूप में (2018)	65	36	11.1	50

स्रोत : विश्व विकास संकेतक 2019

- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली-चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएँ हैं—



- इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को आयुष (AYUSH) भी कहते हैं (आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथिक)। भारत में वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 4,095 आयुष अस्पताल और 27,951 दवाखाने और 8 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं।
- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएँ हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती हैं।

(c) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारिक संरचना के सूचक : एक मूल्यांकन (An assessment of Health and Health Infra-indicators)

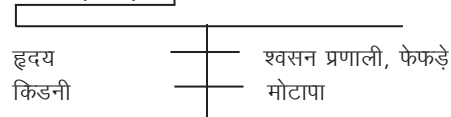
विशेषज्ञों की यह राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक में सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए,

सूची 3.5 यह बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.9 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 में एवं 2019-20 में जी.डी.पी. का क्रमशः 2.1% तथा 1.3%) है। यह अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है।

- एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग पाँचवाँ हिस्सा निवास करता है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20 प्रतिशत बोझ (GDB) है।

- विश्व रोग भार (GDB) एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताये सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं।

- वर्ष 2017 के एक अध्ययन में लगभग दो-तिहाई जी. बी.डी. को दिखाया गया है, जिसे अब रोग का कुल बोझ के नाम से जाना जाता है, जीवन शैली से जुड़ी गैर-संचारी बीमारियों के कारण होता है—



- डायरिया, श्वसन-प्रणाली (Respiratory System) और सामान्य संक्रामक रोग भारत में होने वाली कुल मृत्यु का छठा हिस्सा है।
- वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 4.1 मिलियन शुरुआती मृत्यु होती है, जिसमें से अकेले भारत में 1.1 मिलियन मौतें हुई हैं। इसके अतिरिक्त गत दो दशकों में कैंसर (8 प्रतिशत) और दुर्घटना (11 प्रतिशत) से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- वर्तमान में 20 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि केवल 38 प्रतिशत प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है और केवल 30 प्रतिशत प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार होता है।

(d) शहरी-ग्रामीण तथा धनी-निर्धन विभाजन (Urban-Rural and Poor-Rich Division)

भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल (प्राइवेट क्षेत्रक सहित) स्थित हैं। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.13 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30 प्रतिशत बेड उपलब्ध हैं।

- अतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारिक संरचना उपलब्ध नहीं है। इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है।

- ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक एक लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल हैं जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 3.6 अस्पतालों की है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित **प्राथमिक चिकित्सा** केंद्रों में **एक्स-रे** या **खून** की जांच जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि किसी शहरी के लिए ये **बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल** का निर्माण करती हैं।
- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्य **स्वास्थ्य सुविधाओं** में अपेक्षाकृत पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित **चिकित्सा** से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

ग्रामीणों को - **शिशु चिकित्सा** **स्त्री रोग चिकित्सा**
संवेदनाहरण (Anesthesia) **तथा प्रसूति विद्या (obstetrics)**
 जैसे विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध नहीं है।

- इसके बावजूद 530 मान्यता प्राप्त **मेडिकल कॉलेजों** से प्रतिवर्ष 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं, ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार **भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों** में रहने वाले **निर्धनतम** लोग अपनी आय का 12 प्रतिशत **स्वास्थ्य सुविधाओं** में खर्च करते हैं, जबकि **धनी केवल 2 प्रतिशत** खर्च करते हैं।

(e) महिला स्वास्थ्य (Women Health)

भारत की **जनसंख्या** का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। पुरुषों की तुलना में उन्हें **शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों** में भागीदारी और **स्वास्थ्य सुविधाओं** के क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- देश में शिशु-लिंग अनुपात 2001 में 927 से 919 की गिरावट, भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करता है।
- 15-19 वर्ष से कम की लगभग पाँच प्रतिशत लड़कियाँ न केवल शादीशुदा हैं बल्कि कम-से-कम एक बच्चे की माँ भी हैं।
- 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा **महिलाओं** में 50 प्रतिशत से ज्यादा **रक्ताभाव (Anemia)** और **रक्तक्षीणता** से ग्रसित हैं। यह बीमारी **लौह-न्यूनता (Iron deficiency)** के कारण होती है।
- 2005 के बाद से इसमें गिरावट नहीं आई है। जी. बी.डी. अध्ययन 2017 की रिपोर्ट है कि वर्ष 2007 और 2017 दोनों वर्षों में नवजात विकारों (Neonatal disorders) के कारण असामयिक मृत्यु बहुत अधिक थी।
- स्वास्थ्य** एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और एक बुनियादी मानवाधिकार है। सभी नागरिकों को बेहतर

स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, यदि **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं** विकेंद्रित हों।

- रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष में सफलता **शिक्षा** और **कार्यकुशल स्वास्थ्य** आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। इसीलिए **स्वास्थ्य** और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है।

- ➔ **स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों** की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं (Primary Health Facilities) पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाना है।

व्यावसायिक संरचना (Business Structure)

लोग तरह-तरह के काम करते हैं। कुछ लोग **खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों** आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं, तो कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। **घर पर होने वाले** काम अब **बुनाई, फीते बनाना** या **हस्तकलाओं** जैसे पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इनमें **सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग** के प्रोग्राम बनाने जैसे **आधुनिक काम** भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो **प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों (Technological changes)** ने गांव के घर में ही **औद्योगिक उत्पादन** संभव बना दिया है।

- किसी कार्य से जुड़ा रहना, हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति (Feeling significant) प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं।
- प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से **राष्ट्रीय आय** में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न **आर्थिक क्रियाओं** में भाग लेकर देश के **आर्थिक विकास** में हिस्सेदार बनता है। यही सही अर्थों में **आजीविका उपार्जन (Earning a livelihood)** है।
- व्यक्ति केवल अपने लिए काम नहीं करते; अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। कार्य के इसी महत्त्व को समझ कर महात्मा गांधी ने **शिक्षा** और **हस्तकलाओं** सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था।
- कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में **रोजगार की प्रकृति** और **गुणवत्ता** के विषय में एक

गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने **मानवीय संसाधनों** को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलती है।

- इससे विभिन्न **उद्योगों** तथा **क्षेत्रों** के **राष्ट्रीय आय** में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत-वर्गों, **बाल-श्रमिकों** आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे, जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। — “(महात्मा गांधी)”

■ श्रमिक और रोजगार (Labour and Employment)

किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम **वस्तुओं** और **सेवाओं** का कुल **मौद्रिक मूल्य** इसका 'सकल घरेलू उत्पाद' कहलाता है।

देश का निवल (Net) अर्जन धनात्मक हो सकता है (यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे) या ऋणात्मक हो सकता है (यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे) या शून्य हो सकता है (यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हों)। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं (+ या -) तो उस वर्ष के लिए देश का **सकल घरेलू उत्पाद** (GDP) प्राप्त होता है।

- ➔ **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** (GNP) में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को **आर्थिक क्रियाएं** कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो **आर्थिक क्रियाओं** से संलग्न होते हैं, **श्रमिक** कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

- इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि

शारीरिक कष्टों खराब मौसम त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते, तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है।

- इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी **श्रमिक** ही मानते हैं।
- जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं, उन सबको **रोजगार** में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

- वर्ष 2017-18 में भारत की कुल **श्रम-शक्ति** (Labour Force) का आकार लगभग 471 मिलियन आँका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसीलिए **ग्रामीण श्रमबल** का अनुपात भी शहरी श्रमबल से कहीं अधिक है।

- 471 मिलियन श्रमिकों में **दो-तिहाई श्रमिक ग्रामीण** हैं। भारत में श्रमशक्ति में पुरुषों की बहुलता (majority) है। श्रमबल में लगभग 70 प्रतिशत पुरुष तथा शेष (इसमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है) महिलाएं हैं।

- ग्रामीण क्षेत्र** में महिला श्रमिक कुल **श्रमबल का एक तिहाई** हैं, तो **शहरों** में केवल **20 प्रतिशत महिलाएं** ही **श्रमबल** में भागीदार पाई गई हैं।

महिलाएं -

खाना बनाने पानी लाने ईंधन बीनने के साथ-साथ खेतों में भी काम करती हैं।

- उन्हें **नकद** या **अनाज के रूप में मजदूरी** नहीं मिलती। कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता।

(i) लोगों की रोजगार में भागीदारी (People's Participation in Employment)

श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में **रोजगार** की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है यह जानने में सहायक है कि **जनसंख्या** का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है, तो इसका तात्पर्य है जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी।

- ➔ यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो, तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से **आर्थिक क्रियाओं** में संलग्न नहीं है।

सूची

भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, 2017-2018			
कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात	संपूर्ण	ग्रामीण	शहरी
पुरुष	52.1	51.7	53.0
स्त्री	16.5	17.5	14.2
संपूर्ण	34.7	35.0	33.9
स्रोत : भारत सरकार (2019)			

- जनसंख्या** शब्द का अभिप्राय किसी **क्षेत्र विशेष** में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है।